



घूँघट की बग़ावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 09

गोरखपुर, 24 अगस्त 2025 रविवार

पृष्ठ : 6

मूल्य : 2

धर्मस्थल प्रकरण: अदालत से जमानत मिलने के बाद

यूट्यूबर को भेजा गया समन

बंगलुरु। कर्नाटक के धर्मस्थल मामले में पुलिस ने अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद यूट्यूबर एम.डी. समीर को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। समीर विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के दायरे में हैं। पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को मंगलुरु की एक अदालत द्वारा समीर को अग्रिम जमानत दिये जाने के बाद यह नोटिस बल्लारी स्थित उनके आवास पर चिपकाया गया। धर्मस्थल मामले से संबंधित सामग्री यूट्यूब पर डालने को लेकर समीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि समीर के खिलाफ धर्मस्थल थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 240 (गलत जानकारी देना) और 353(1)(बी) (शांति भंग करने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, समीर ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने बिना किसी सबूत के कथित तौर पर अनेक आरोप लगाये थे। समीर ने दावा किया था कि उनके वीडियो उन मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया नजरअंदाज कर देता है। अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय समीर को जांच में सहयोग करने और भड़काऊ बयान देने से बचने का निर्देश दिया था।



उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन का चुना जाना लगभग तय

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अब सरकार और विपक्ष के प्रत्याशियों के मध्य मुकाबला होना तय हो गया है। सरकार द्वारा सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इंडी ब्लाक ने भी सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बार उपराष्ट्रपति के पद के दोनों ही प्रत्याशी एक ही प्रान्त तमिलनाडु से आते हैं। कांग्रेस व विरोधी दलों को लगा कि अगर एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के नये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी राधाकृष्णन के माध्यम से दक्षिण विशेषकर तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन को सशक्त करने का प्रयास करेगी क्योंकि जब बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया था तब भाजपा को राजस्थान में राजनैतिक लाभ हुआ था और वहां उसकी सत्ता में वापसी हो गई थी। अब भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी बनाकर तमिलनाडु की जनता व कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है।

जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, दो भर्ती



अहमदाबाद। गुजरात के आणंद जिले में शुक्रवार को एक खाद्य प्रसंस्करण कारखाने के टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि खंबात तालुका के सोखदा गाँव में एकता फ्रेश फूड कंपनी के अपशिष्ट उपचार संयंत्र के टैंक में उतरने के बाद दो श्रमिकों की दम घुटने से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दो अन्य श्रमिकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। खंबात ग्रामीण थाने के अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह उस समय हुई जब किशन बैरया (27) नामक मजदूर टैंक में उतरा और गैस की विषाक्तता के कारण बेहोश हो गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद, किशन को बचाने गए अरविंद (63) भी गैस की चपेट में आ गया। अधिकारी ने बताया कि दो अन्य मजदूर भी गैस से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया जहां किशन बैरया तथा अरविंद को मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

आवारा कुत्तों के लिए बनाए जाएंगे फीडिंग सेन्टर

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आवारा कुत्तों के लिए आवासीय समितियों के सहयोग से आहार स्थल (फीडिंग सेंटर) बनाए जाएंगे। लोग इन्हीं आहार स्थल पर कुत्तों को भोजन करा सकेंगे। इस प्रकार के फीडिंग सेंटर आबादी से थोड़ी दूरी पर खाली और एकांत जगहों पर बनाए जाएंगे।

शहर में इस समय अनुमानित करीब 1.20 लाख आवारा कुत्ते हैं।

नगर निगम की ओर से एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों के तहत करीब 96 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है।

पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिर्फ काटने वाले कुत्तों को ही पकड़ कर सेंटर में रखा जाएगा। अन्य सामान्य कुत्तों का टीकारण और नसबंदी कर उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाएगा।



उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी प्रावधान है कि काम में बाधा डालने पर आम नागरिक से 25 हजार रुपये और एनजीओ पर एक लाख रुपये



तक का जुर्माना लगाया जाए। आदेश के तहत अब आवासीय समितियों के सहयोग से आहार स्थल बनाए जाएंगे। इसके लिए टीम बनाकर सर्वे कराया जाएगा।

कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ईडी के छापे में करोड़ों नकद व आभूषण मिले

बंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को शनिवार को एक अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में 31 जगहों पर दो दिनों तक चली तलाशी के बाद यह गिरफ्तारी की। जाँच में एक बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क का पता चला, जिसमें दुबई से संचालन और कई कैसीनो से जुड़े लिंक शामिल थे। 22 और 23 अगस्त को की गई छापेमारी बंगलुरु, हुबली, मुंबई, जोधपुर, गोवा और गंगटोक जैसे शहरों में की गई। इसके अलावा, पाँच प्रसिद्ध कैसीनो, बिग डेडी कैसीनो, ओशन रिवर्स कैसीनो, पीपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और पीपीज कैसीनो गैलर्ड पर भी छापेमारी की गई। ईडी के अनुसार, वीरेंद्र किंग 567 और राजा 567 जैसे नामों से कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहा था। उसका भाई, केसी. थिप्पेस्वामी, दुबई स्थित तीन कंपनियों, डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज के माध्यम से इन गतिविधियों का बैकएंड प्रबंधन कर रहा था। ये कंपनियाँ सट्टेबाजी के संचालन के लिए गैमिंग से संबंधित कॉल सेंटर सेवाएँ प्रदान करती पाई गई।

अधिकारियों का मानना है कि दुबई स्थित ये गतिविधियाँ अवैध धन



के शोधन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमावड़े का केंद्र थीं। व्यापक तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने लगभग ₹12 करोड़ नकद, जिसमें ₹1 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी शामिल है, जब्त किया। इसके अलावा, लगभग ₹6 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण, 10 किलो चाँदी के बर्तन

स्टालिन का बीजेपी पर तीखा वार

तमिलनाडु को फंड देने से क्यों इनकार ?

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा प्रहार करते हुए केंद्र सरकार पर राज्य प्रशासन के लिए परेशानी पैदा करने और धन का उचित हिस्सा आवंटित करने से इनकार करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति है और अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में, तमिलनाडु कई क्षेत्रों में सबसे आगे है।



बी ज्यादा समय से तमिलनाडु आरक्षण नीति को लागू कर रहा है और कई प्रगतिशील कानून व योजनाएँ लागू कर रहा है। इसकी नींव द्रविड़ आंदोलन ने रखी थी।

स्टालिन ने आगे कहा कि कड़ी वित्तीय पाबंदियों के बावजूद, तमिलनाडु ने 2024-25 में 11.19% की दोहरे अंकों की विकास दर हासिल की है, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपे जाने के खिलाफ तमिलनाडु के विरोध के बाद, भारत के विभिन्न राज्यों में इसी तरह के हिंदी विरोधी आंदोलन हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संघवाद के भीतर राज्य की स्वायत्तता का सिद्धांत ही भारत की एकता और विविधता दोनों को मजबूत करता है। आत्मनिर्भर राज्यों के प्रयासों से ही एक अखंड भारत वास्तव में मजबूत बन सकता है।

स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ नेताओं ने समानता, सामाजिक न्याय और महिला अधिकार जैसे महान सिद्धांतों के लिए अथक प्रयास किया। अन्ना और कलैगनार दोनों ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया जिससे जीवन के हर क्षेत्र में लोगों का उत्थान हुआ।

बाढ़ प्रभावित गाँवों में पहुँचे केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किया संवाद

अशोकनगर/मुंगावली। पिछले तीन दिनों से लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर जिले के मुंगावली स्थित बाढ़ प्रभावित बरखेड़ा जमाल और गोरा बहादुरपुर गाँव पहुँचे। जहाँ उन्होंने बाढ़ एवं अतिवर्षा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं और राहत व पुनर्वास कार्यों की स्थिति का निरीक्षण किया। केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने आज मौके पर उपस्थित आपदा प्रभावित परिवारों को अपने हाथों से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन द्वारा प्रभावितों को हर संभव उपयुक्त राहत राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त आपदा में बरखेड़ा जमाल गाँव में 39 परिवार प्रभावित हुए हैं तथा 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और गोरा बहादुरपुर गाँव में भी कई परिवार अतिवर्षा और बाढ़ से प्रभावित हैं। केन्द्रीय मंत्री ने प्रभावितों से बिजली, पानी और राशन

- ▶ राहत व पुनर्वास कार्यों का किया निरीक्षण
- ▶ प्रभावितों को दी आर्थिक सहायता



वितरण की स्थिति की जानकारी ली और फसलों की क्षति व मकानों के नुकसान का शीघ्र मुआवजा

दिलाने का आश्वासन दिया। अपने संसदीय क्षेत्र के चार दिवसीय प्रवास में केन्द्रीय मंत्री सिंधिया लगातार

मरीज के परिजनों ने एक्सपायर्ड डेट की दवा देने का आरोप

बस्ती। मालवीय रोड स्थित एक नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोर पर मरीज के परिजनों ने एक्सपायर्ड डेट की दवा देने का आरोप लगाया है। नर्सिंग होम पहुँचे परिजनों ने हंगामा किया। बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने उसके मेडिकल स्टोर की दवा होने से इंकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि वह इस बात की शिकायत सक्षम अधिकारी से करेंगे। नर्सिंग होम पहले से विवादों में है। परिजनों का कहना था कि कुछ दिन पहले वह अपने मरीज को महिला चिकित्सक को दिखाया तो उन्होंने कई दवाएँ लिखी थी। दवा नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोर से खरीदी और दवा लेकर घर चली गई। दो दिन दवा खाने के बाद उसे कुछ समस्या हुई तो घर वालों ने दवा की जांच की। यह देखकर उन लोगों के होश उड़ गए कि दवा एक्सपायर हो चुकी थी। इसकी शिकायत लेकर परिजन शुक्रवार को नर्सिंग होम पर आए थे। ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोर की जांच कराई जाएगी।

और चार महंगे वाहन जब्त किए गए। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17 बैंक खाते और दो बैंक लॉकर जब्त कर लिए गए। वीरेंद्र के भाई के.सी. नागराज और नागराज के बेटे पृथ्वी एन. राज के आवास से संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। विधायक को 23 अगस्त, 2025 को गंगटोक से गिरफ्तार किया गया था, जहाँ कथित तौर पर वह अपने सहयोगियों के साथ क्षेत्र में एक जमीनी कसौती को पट्टे पर लेने की संभावना तलाशने गए थे। ईडी ने कहा कि आपत्तिजनक सबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के खिलाड़ियों से जुड़े रनकदी और धन के जटिल स्तरर की ओर इशारा करते हैं।

वीरेंद्र को गंगटोक में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और आगे की कार्यवाही के लिए बंगलुरु लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्रदान की गई। वीरेंद्र के अलावा, उनके भाई के सी थिप्पेस्वामी और भतीजे पृथ्वी एन राज भी ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय हस्तांतरण में उनकी भूमिका के लिए जाँच के घेरे में हैं। जाँचकर्ताओं ने पाया कि इनमें से कई संचालन दुबई से संचालित किए जा रहे थे।

उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी

यह लड़ाई नहीं, विचारों का टकराव है...

इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा का टकराव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह इस विचारधारा से असहमत हैं, न कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से। एएनआई से बात करते हुए, इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह कोई लड़ाई नहीं, बल्कि विचारों का टकराव है... दूसरा पक्ष यह प्रचार कर रहा था कि यहाँ एक व्यक्ति है जो जीवन भर आरएसएस का पूर्ण सदस्य रहा है, इसलिए मैं उस विचारधारा से असहमत हूँ, सीपी राधाकृष्णन जी से नहीं।

बी सुदर्शन रेड्डी ने आगे कहा कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से उनका कोई निजी विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन और मेरे बीच कोई निजी मतभेद नहीं है। हम एक-दूसरे से कभी मिले भी नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता था कि यह एक सभ्य मुकाबला हो, व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग-अलग विचारधाराओं के बीच। रेड्डी ने वैचारिक मतभेदों को उजागर करते हुए कहा कि मुझे किसी विचारधारा को पसंद या नापसंद करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से यह (आरएसएस) काम करता है, उससे मेरे गंभीर मतभेद हैं, क्योंकि मैं एक उदार संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ। मैं धर्मान्तरप्रेक्षता, सामाजिक न्याय और बाबासाहेब की बंधुत्व की विचारधारा में विश्वास करता हूँ।

गत गुरुवार को, भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। राकांपा (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और गठबंधन के कई अन्य नेता भी मौजूद थे।

इससे पहले, इंडिया ब्लॉक ने 9 सितंबर को होने वाले आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार चुना था। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद राष्ट्रीय राधधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की। रेड्डी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।



तीन दिन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं जबकि इन क्षेत्रों में बारिश अभी भी जारी है। वह मौके पर जाकर पुनर्वास कार्यों की प्रगति देख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुँच सके। गत शनिवार को मुंगावली के इन बाढ़ प्रभावित गाँवों में सिंधिया ने राहत कैम्प में रह रहे परिवारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने वहाँ उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री, बिजली-पानी एवं आवश्यक व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाएँ। इस दौरे में सिंधिया के साथ स्थानीय विधायक, मंडल अध्यक्ष तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय मंत्री आज गुना शहर पहुँचकर आपदा प्रभावित वीआईपी कॉलोनी, न्यू सिटी कॉलोनी, शिव कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह आपदा में अपनों को खो चुके परिवारों के घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे तथा उन्हें उचित मुआवजा राशि भी प्रदान करेंगे।



एडीएम की ओर से गुंडा एक्ट के तहत जारी नोटिस रह मात्र दो मामलों में नाम आने से किसी को गुंडा की परिभाषा में नहीं : हाइकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक मामलों में नाम दर्ज होने के आधार पर किसी को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने ललितपुर के एडीएम की ओर से गुंडा एक्ट के तहत जारी नोटिस को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की याचिका पर दिया।

याची सौरभ कुमार के खिलाफ 30 जून 2025 को ललितपुर के एडीएम ने दो मुकदमों व एक बीट रिपोर्ट के आधार पर यूपी गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी किया था। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता ने दलील दी कि केवल दो आपराधिक मामलों और एक बीट रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार का नोटिस जारी करना कानून का उल्लंघन है। गोवर्धन बनाम राज्य (2023) के मामले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मात्र दो मामलों में नाम आने से किसी को गुंडा की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने ललितपुर के एडीएम की ओर से जारी नोटिस को प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

दो दिवसीय डोल मेले का आयोजन परंपरागत ढंग से संपन्न

कसया,कुशीनगर। नगर में दो दिवसीय डोल मेले का आयोजन बुधवार की शाम को हर्षोल्लास के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। प्रशासन ने नगर के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी। आयोजक अपने-अपने अखाड़ों के साथ नगर में भगवान के स्वरूप की झांकियों के साथ हैरतअंग्ज करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले में एसडीएम डॉ. संतराज सिंह और सीओ कुंदन सिंह पल-पल की खबर लेते रहे।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नगर में दो दिवसीय डोल मेले का आयोजन परंपरागत ढंग से किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से शुरू किया गया। पूरे नगर से 12 आयोजकों ने भव्य झांकियां और अखाड़ा निकालकर करतब दिखाए। वहीं आर्केस्ट्र में नर्तकियों ने युवाओं का मनोरंजन किया। सभी अखाड़े नगर भ्रमण करते हुए अपने स्थानों पर वापस हुए। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां, भगवान के रूप में सजाए

► **जखनिया विधायक ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण अस्पताल में मचा हड़कंप, प्रभारी चिकित्सक को लगी फटकार**

दुर्व्यवस्था पर भड़के, स्वास्थ्य सेवाओं व दवाओं के विषय में ली जानकारी

जखनियां, गाजीपुर। सुभासपा के जखनिया विधायक बेदी राम ने गत दिनों शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत को देखा। करीब एक घंटे तक चले निरीक्षण में मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं व दवाओं को लेकर जानकारी ली। मरीजों की ओर से बाहर से दवा खरीदने की शिकायत सुनकर विधायक भड़क उठे। नाराज विधायक ने प्रभारी चिकित्सक डॉ. जोगेंद्र यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि जब सरकार वेतन और संसाधन मुहैया करा रही है, तो मरीजों को मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए। दूसरी तरफ सीएचसी प्रभारी ने विधायक पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने व वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। निरीक्षण के दौरान विधायक की ओर से अस्पताल में तैनात स्टाफ और संचिदा कर्मियों की उपस्थिति व कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़ा

मास्टर प्लान 2031 लागू होने के बाद प्रदेश भर में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हुए एक समान

प्रयागराज। विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने निर्माण एवं विकास उपविधि में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने जहां का लेआउट पास है, वहां के 100 वर्ग मीटर के भवन स्वामियों को भी नौ, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है। इस फैसले से शहर के करीब 50 हजार से अधिक मकान मालिकों को लाभ मिलेगा।

मास्टर प्लान 2031 लागू होने के बाद प्रदेश भर में मॉडल बिल्डिंग बायलॉज एक समान हो गए हैं। पहले अलग-अलग प्राधिकरणों में अलग नियम थे। नए प्रावधान के तहत 24 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित मिश्रित भूखंड का मकान मालिक अब अपने मिश्रित भूखंड भू-उपयोग वाला मानचित्र स्वीकृत कराकर दुकानें या छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। जिन लोगों ने पहले से अपने घरों में दुकानें खोली हैं, उन्हें अब आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी। जिस मकान के सामने नौ, 12, 18 या 24

किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि जो कर्मचारी इयूटी से गावब रहते हैं, उनकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही अस्पताल की साफ-सफाई और अन्य कक्षों की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉ. जोगेंद्र यादव को हिदायत दी कि मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भविष्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इसलिए इस पर समझौता संभव नहीं है। विधायक दोपहर 12 बजे सीएचसी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत की। साथ ही ओपीडी व दवाओं के रख-रखाव की व्यवस्था को देखा। दूसरी ओर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉ. जोगिंदर

► पीडीए ने किया निर्माण एवं विकास में उपविधि में बदलाव



मीटर चौड़ी सड़कें हैं, वहां भी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू हो सकेगी। नए नियम से बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और किराना स्टोर, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल समेत छोटे व्यवसाय आसानी से शुरू हो सकेंगे। इस निर्णय से पीडीए की आय में भी बढ़ोतरी

लापरवाही के कारण संसाधन होने के बाद भी उसका लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर बाहर की जांच और दवाएं लिख रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी खराब कर दिया गया है। भोजनालय में ताला लटक रहा था। बेड रंदि थे। मेरे पहुंचने पर डॉक्टरों को बुलाया हाजिरी लगवाया जा रहा था। पहुंचने पर मुझसे ही बतमीजी की गई। यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है। साथ ही वहां जनता भी मौजूद थी। फिलहाल, निरीक्षण और वहां की स्थिति से मैंने डीएम और सीएमओ से अवगत करा दिया है।



-बेदीराम, विधायक

यादव ने विधायक के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान विधायक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अस्पताल की कुछ वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाया। कहा कि यह कृत्य किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता और इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की जाएगी। अस्पताल को कबाड़खाना जैसा बना दिया गया है।

नई उपविधि 2025 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जिस इलाके का लेआउट पीडीए से पास है, उन इलाकों के नौ, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़क पर कॉमर्शियल गतिविधि की अनुमति जरूरी होगी। लोगों को इस नए नियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

डॉ. अमित पाल शर्मा, उपाध्यक्ष, पीडीए

होगी। व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा। जहां का लेआउट पास है वहां एक रुपये जमा कर मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। जिन्होंने पहले से दुकानें खोली है, उन्हें भी मानचित्र पास कराना होगा।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुशासन पुलिस सेवा की नींव: विक्रांतवीर

► **एसपी ने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का किया अवलोकन**
► **रिक्रूट्स की समस्याओं और आवश्यकताओं से हुए रूबरू**

देवरिया। एसपी विक्रांत वीर ने गत रविवार को पुलिस लाईंस स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे आरक्षियों की गतिविधियों, अनुशासन और प्रशिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था देखी। निरीक्षण के दौरान एसपी ने बैरक, भोजनालय, आरटीसी कार्यालय और प्रशिक्षण से जुड़े अन्य स्थलों की स्थिति देखी। उन्होंने रिक्रूट्स से संवाद कर उनके अनुभव, समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। एसपी ने कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुशासन पुलिस सेवा की नींव है। प्रत्येक आरक्षी को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना से प्रशिक्षण लेना चाहिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को शारीरिक दक्षता, मानसिक मजबूती और नैतिक मूल्यों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि एक सशक्त और संवेदनशील पुलिस बल के निर्माण के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने साफ-सफाई, रहन-सहन, स्वास्थ्य सुविधाओं और भोजन व्यवस्था का भी मूल्यांकन किया। संतोष जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निरंतर सुधार और लापरवाही से बचने के निर्देश दिए।

गोष्ठी संपन्न

देवरिया। विश्व मच्छर दिवस पर बुधवार को जिला मलेरिया कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों डेंगू और मलेरिया, से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। वेक्टर बार्न कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉ. हरेंद्र कुमार ने कहा कि बारिश के मौसम में जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए घर के पास पानी नहीं जमा होने दें।

► मुझे तो बस चलते जाना है...पदयात्राओं ने कद बढ़ाया

सहयोगियों को फायदा दिलाया, संभावना दिखते ही सड़क पर उतर जाते हैं राहुल

मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया
मजरूह सुलतानपुरी की ये लाइनें वर्तमान राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया है जब महात्मा गांधी दिसंबर 1914 के अंत में अवतरित होती है और उसके बाद से देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। इलीट लोगों के क्लब लगने वाली कांग्रेस पार्टी एक मॉस आर्गनाइजेशन में बदल जाती है। जवाहरलाल लाल नेहरू ने गांधी जी का जिक्र करते हुए इसमें बताया है कि गांधी जी ने सबसे बड़ा बदलाव जो भारतीय राजनीति में किया वो ये था कि उन्होंने लोगों के मन में जो खौफ था। अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर जो डर था। गांधी ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर और लोगों के मानस में एक बड़ा बदलाव किया। अंग्रेजों के डर को खत्म कर दिया। उन्होंने लोगों को अभय की बात सिखाई। अभय मतलब जिसको भय नहीं है। जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने देश की संसद में खड़े होकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अभय मुद्रा का बार बार जिक्र किया। शिव की तस्वीर में और कांग्रेस का चुनाव चिह्न अभय मुद्रा है और ये निडर रहने की बात करता है। इसी दौरान राहुल ने कहा कि इस्लाम में दोनों हाथों से दुआ करना भी एक तरह की अभय मुद्रा है। वैसे तो देश में गौतमबुद्ध, शंकराचार्य, गुरुनानक से लेकर महात्मा गांधी और विनोबा भावे तक की पदयात्रा का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जब चला करते थे तो लोग जुड़ते चले जाते थे। वो कारवां इतना बड़ा हुआ करता था कि परिवर्तन की दिशा इस देश को आजादी में ले गई। इससे इतर राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी पदयात्रा निकाली गई। यात्राएं इस देश की भीतर बहुत हुई हैं और हर यात्रा का कोई न कोई प्रतिफल उस राजनीतिक दल या नेता के भीतर जरूर आया है। देश में अब तक कई सियासी यात्राएं हुई हैं, उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय या राज्य सियासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। लोगों ने उनसे संवाद बनाया। उनके अपने सरोकार लोगों से जुड़े और एक संवाद की स्थिति ने सत्ता तक भी पहुंचाया है।

अब राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले

आजादी की लड़ाई से आजादी के बाद तक विभिन्न दलों की लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कहीं न कहीं रंग लाती दिखी है। अब राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। अब राहुल गांधी वोट चोरी के सवाल को खड़ा करके बिहार के सासाराम से निकले हैं। 17 अगस्त शुरू हुई यह यात्रा 16 दिनों में बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल इस दौरान 1300 किमी की दूरी तय करेंगे। राहुल की वोट अधिकार यात्रा उनकी अब तक की पांचवी बड़ी यात्रा होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। बर्फ और ठंड में टी शर्ट में उनका खड़े होना एक पहचान बन गई थी। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई तक और उसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में दिखा। कांग्रेस की सीटें बढ़ीं। बीजेपी की सीटें कम हुईं। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए शायद सबसे बड़ी अभिपरीक्षा शुरू हो रही है। पहले की राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं थी। न कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे था। लोगों को लग रहा था कि राहुल कुछ कर रहे हैं तो यात्रा पर निकले हैं। लोकसद दोनों यात्राओं से राहुल गांधी की छवि बढ़ेली। कांग्रेस और उससे भी कहीं ज्यादा उनके सहयोगियों को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में नतीजा भी नजर आया।

उत्तर भारत में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का 'उत्तर' ढूढ़ने निकले

पिछले दिनों नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी से अपेक्षा बढ़ गई हैं। राहुल गांधी खास हमलावर तेवर दिखा रहे हैं। सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे है। वोट चोरी को सही मायनों में उन्होंने एक अखिल भारतीय मुद्दे में तब्दील कर दिया है। ऐसे में ये यात्रा क्या रंग लाती है। कांग्रेस और बिहार के गठबंधन की विधानसभा चुनाव में कैसे फायदा पहुंचाती है। 80 सीटों वाले यूपी, 48 सीटों वाले महाराष्ट्र और 42 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी गिरी। लेकिन 40 सीटों वाले बिहार ने मोदी को बचा लिया। अगला युद्ध उसी बैटल ग्राउंड में है। जहां 90 के दशक के बाद कांग्रेस कभी उठ नहीं सकी है। राहुल जहां मोदी के साथ रेस लगाने



के लिए उतरे हैं वहां की पॉलिटिकल पिक्चर पर थोड़ा नजर डालें तो। राहुल गांधी की बिहार यात्रा का मकसद बहुजन समाज को आकर्षित करना और नीतीश कुमार की जदयू व चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में संघ लगाना है। राहुल ने जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा हटाने, अत्याचारों को उजागर करने और धर्मनिरपेक्षता को मिलाकर एक नई पहचान गढ़ी है। वो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और दीपंकर भट्टाचार्य की सीपीआरएमएल की लाइन पर हैं।

संभावना दिखते ही सड़क पर उतर जाते हैं राहुल

राजनीति में अपने शुरूआती दिनों में भी राहुल ने पश्चिम यूपी के भट्टा-पारसोल में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पदयात्रा की थी। उनकी यात्रा को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के लिए एक और चुनौती के रूप में देखा गया था। राज्य सरकार ने युवा सांसद को 9 जुलाई को पड़ोसी अलीगढ़ जिले में किसानों की महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जो जबरन भूमि अधिग्रहण को लेकर इसी तरह के आक्रोश का सामना कर रहे थे। मंदिर में राहुल ने ग्रामीणों से कहा था कि मैंने आज तक एक भी किसान नहीं देखा जो विकास के खिलाफ हो। मगर विकास के नाम पर आपकी मूल्य का करो हिसाब।

देवरिया से दिल्ली तक किसान यात्रा

किसानों के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देवरिया से दिल्ली तक 'किसान यात्रा' की। 30 दिनों के दौरान वह लगभग एक महीने में 2,500 किलोमीटर की दूरी तय किया था। राहुल देवरिया के पंचलारी गांव से अपनी यात्रा की शुरूआत की थी। यात्रा के दौरान पार्टी वर्कर्स घर-घर जाकर घरों के मुखिया से किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। यात्रा के लिए 250 मिनी रथ तैयार किए गए। तब यूपी में कांग्रेस ने नारा दिया था कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ...समर्थन मूल्य का करो हिसाब।

जहाँ मिली राहुल को 'आग जैसी ताकत'

2015 में उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। इसका मकसद यह बताना था कि 2013 में आई आपदा के बाद स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर पहुंचे राहुल गांधी

ने कहा था कि यहाँ आकर मुझे आग जैसी शक्ति मिली है। राहुल ने कहा कि मैं मंदिर में गया, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब मैं मंदिर के भीतर गया तो मुझे आग जैसी शक्ति मिली। इसके सा0थ ही उन्होंने कहा कि जब ये आपदा आई तो जो यहाँ अफसर काम करते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके बारे में काफी नकारात्मक बातें कही गईं लेकिन आपदा आने के बाद से अफसरों ने, सेना ने, पुलिसवालों ने बहुत अच्छे काम किया।

पिछली यात्रा से कितनी अलग

भारत जोड़ो यात्रा से बहुत अलग है वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी अलग है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरा फोकस राहुल गांधी पर था। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के नेता खासकर तेजस्वी यादव बराबरी से शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल पूरी यात्रा के दौरान पैदल चले थे। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल जीप में रहे और आम लोगों से सीधे मिलने नहीं गए। राहुल की ये यात्रा उस समय हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांगों को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नए ड्राफ्ट रोल में जिनके नाम हटाए गए हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके कुछ महीनों पहले जब अचानक से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तो तमाम संदेह उठने लगे।

नए प्रश्न पत्र के साथ सामने आए राहुल

राहुल गांधी 7 अगस्त को सामने आए और उनके हाथों में आयोग का दिया वोटर लिस्ट लिए मीडिया को 2024 पोल डेटा का एक ऑनलाइन प्रजेंटेशन करके दिखाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कैसे महाराष्ट्र में पांच महीने के अंदर 1 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया। चुनाव आयोग ने पोल डेटा का सॉफ्ट कॉपी देने से मना कर दिया। कांग्रेस को पेपर सीट निकालने पड़े। जो पेपर निकला भी वो ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर मशीन से निकाल सकते हैं। राहुल गांधी ने ये भी बताया कि चुनाव आयोग चाहता है कि सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर दिया जाए। जिससे एकदु वोटर गायब हो जाए और उस पर सवाल न उठे। कांग्रेस पार्टी ने 30-40 लोग लगाकर, महीने लगाकर लाख वोट चोरी होने का खुलासा किया है। सवाल हमारे डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का है और एक एक वोट के हक का है। ऐसे में आज हम विपक्ष के आरोपों, चुनाव आयोग के जवाब, अगर ये आरोप सही होते हैं तो इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। इस दावे ने देश को चौंका दिया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व 2024 लोकसभा चुनाव की कुछ सीटों के नतीजों पर कांग्रेस को संदेह जताती रही है, उसे बल मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, तो माना गया कि राहुल की मेहनत रंग लाई है। इसी से यह संभावना भी टटोली गई कि क्या एक और यात्रा हो सकती है।

सहयोगियों के लिए फायदमंद राहुल की यात्रा

बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित, आदिवासी) फॉर्मूला लेकर आई। राहुल के सामाजिक न्याय और आरक्षण बचाओ वाले एजेंडे के साथ मिलकर अखिलेश ने काम किया और इसका सीधा फायदा आपदा से नजर आया। वैसे ही कुछ राहुल ने मायावती सरकार के दौरान साल 2007 में भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चलाया था। कहा तो ये भी जाता है कि इसका फायदा 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उठाया था। तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक में कांग्रेस के हाथिये पर होने के बावजूद सहयोगियों की तरफ से खासी तवज्यो दी जा रही है। अब बारी बिहार की है और यहां तो पहले से ही ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी और राहुल बगल की सीट पर बैठ राज्य के सियासी समीकरण में कौन लड़ें, कौन सहयोगी की भूमिका को साफ कर चुके हैं। राजद का पुराना संगठन है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी विलयर है। इसका फेस राहुल है। बिहार चुनाव में वैसे तो अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। लेकिन राहुल की यात्रा कांग्रेस और उनके सहयोगियों को कितनी सफलता दिला पाएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।

आज स्थिति यह है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत केवल समय और धन की बर्बादी ही नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव और विघटन का कारण बन रही है। स्कूल और कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर इस आभासी दुनिया में डूबते जा रहे हैं। युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा रात-दिन गेमिंग में डूबा रहता है, जिससे उनके व्यक्तित्व और भविष्य पर गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह संकट केवल आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक भी है। दिन-रात स्क्रीन से चिपके रहने वाले युवक चिड़चिड़ापन, अवसाद और एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं। उनमें हिंसक प्रवृत्तियां भी उभर रही हैं।

विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण का कानून सराहनीय

इंटरनेट के विस्तार ने आधुनिक दौर में जीवन को अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए गंभीर संकट भी पैदा किए हैं। इनमें सबसे गंभीर संकटों में से एक है ऑनलाइन गेमिंग या कहें तो मनी गेमिंग की बढ़ती लत। यह सच है कि गेमिंग मनोरंजन का साधन हो सकती है, पर जब इसमें धन का जुड़ाव होता है, तब यह सीधा-सीधा जुए एवं सट्टे के रूप में बदल जाती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग यदि लत बन जाए तो यह संपन्न व्यक्ति एवं परिवार को भी कंगाल कर सकती है। एक आंकड़े के अनुसार देश में एक साल में 45 करोड़ लोगों ने बीस हजार करोड़ गवां दिये हैं। सब कुछ गंवा कर आत्महत्या करने के मामले भी प्रकाश में आते रहे हैं। सवाल इन लालच बेचने एवं जगाने वाली मनी गेमिंग की पारदर्शिता को लेकर भी उठते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं एवं त्रासद विडम्बनाओं के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण का एक विधेयक भारत सरकार इसी मानसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लेकर आई है। जिसे अब गंभीर चर्चा के बिना संसद ने पारित भी कर दिया है। यह विधेयक पैसे से खेले जाने वाले किसी भी ऑनलाइन गेम को गैरकानूनी घोषित करता है। यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि गेमिंग के नाम पर अखंड रूपए का लेन-देन और करोड़ों युवाओं की मानसिक शांति को नष्ट करने वाली प्रवृत्ति दिनोंदिन विकराल रूप ले रही है।

आज स्थिति यह है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत केवल समय और धन की बर्बादी ही नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव और विघटन का कारण बन रही है। स्कूल और कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर इस आभासी दुनिया में डूबते जा रहे हैं। युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा रात-दिन गेमिंग में डूबा रहता है, जिससे उनके व्यक्तित्व और भविष्य पर गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। यह संकट केवल आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक भी है। दिन-रात स्क्रीन से चिपके रहने वाले युवक चिड़चिड़ापन, अवसाद और एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं। उनमें हिंसक प्रवृत्तियां भी उभर रही हैं। कई ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं, जिनमें लगातार आनलाइन गेम खेलते रहने से मना करने पर कोई किशोर हिंसक हो गया और उसने या तो आत्महत्या कर ली या फिर किसी की जान ले ली। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी लत रिश्तों को तोड़ रही है, दोस्ती और पारिवारिक बंधनों को कमजोर कर रही है। एक पूरी पीढ़ी, जिसे राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता इस आभासी जुए में गँवा रही है।

सरकार के मुताबिक, वह ई-स्पोर्ट्स और सोशल



नौकायन रोड पर प्रेमी युगल

विवाहोपरान्त पूर्ण स्वतंत्रता असंभव: सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा सम्बंध में पति/पत्नी के लिए एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होना असंभव है। कोई भी पति या पत्नी यह नहीं कह सकता कि मैं दूसरे पार्टनर से पूरी तरह स्वतंत्र होकर रहना चाहता हूँ। अगर कोई इच्छा रखे तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन है। वो एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक दूसरे से अलग रह रहे कपल की याचिका की सुनवाई के दौरान की। इस कपल के दो छोटे बच्चे थे।

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस केस में दोनों पति पत्नी को बातचीत के जरिए आपसी मनमुटाव को सुलझाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि हर पति पत्नी में तो कुछ तो मतभेद तो होंगे लेकिन अगर इस मामले में दोनों पति-पत्नी साथ आते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनकी क्या गलती है, जो उन्हें एक टूटे हुए परिवार का बोझ झेलना पड़े।

इस मामले में महिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। उसने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। भरे पति सिंगापुर में रहे हैं और मामले को बातचीत से सुलझाना नहीं चाहते। उनकी एकमात्र दिलचस्पी बच्चों की कस्टडी को लेकर ही है। इस पर बेंच ने कहा कि हम सिर्फ आपको नहीं, बल्कि पति-पत्नी दोनों को ही समझा रहे हैं। आप भी अगर बच्चों के साथ पति के साथ रहने के लिए सिंगापुर चली जाती है तो इसमें आपकी क्या दिक्कत है।

महिला ने अपनी कुछ परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि उसके पति की हरकतों के चलते उसका सिंगापुर लौटना बहुत मुश्किल है। सिंगल मदर होने

गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये अवश्य उत्सुक है, जिसमें कोई वित्तीय जोखिम न हो। यहां उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेमिंग का वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही यह हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। लेकिन इसके साथ चिंता का विषय यह भी है कि सुनहरे सब्जबाग दिखाने वाले कई ऑनलाइन गेमिंग एप लत, खेलने वाले आम लोगों के आर्थिक नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले बदकिस्मत उपयोगकर्ता नाकामी के बाद आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। निस्संदेह सरकार ने राजस्व की परवाह न करते हुए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा जोखिम भी उठाया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केवल कानून से इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकेगा? इंटरनेट का विस्तृत दायरा और विदेशी ऑनलाइन ऑपरेटर विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। यह नितांत अपेक्षित है कि वित्तीय प्रणालियों की अखंडता के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस नये कानून को बनाने की जरूरत संभवतः छह हजार करोड़ रुपये वाले महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के बाद महसूस की गई। जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों पर सट्टेबाजी एफ के यूआई स्थित प्रमोटरों के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। जो कथित तौर पर हवाला कारोबार और विदेशों में धन-शोधन के कार्यों में लिप्त बताये जाते हैं। भारत सरकार का यह कदम इसलिए भी जरूरी एवं प्रासंगिक है कि इस उद्योग का टर्नओवर कई आर्थिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक विषयगतियों के साथ कई हजार करोड़ तक पहुंच गया है। विदेशी कंपनियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय होकर भारतीय युवाओं को लुभाने के लिए तरह-तरह के विज्ञापन और प्रलोभन दे रही हैं। इन मंचों पर जीतने की लालच में फंसकर युवा अपने उच्चल भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं बिगाड़ती, बल्कि राष्ट्र की प्रतिा में भी बाधक है, क्योंकि जिन युवाओं को शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रनिर्माण में योगदान देना चाहिए, वे अपना समय और ऊर्जा इन आभासी खेलों में गवां रहे हैं। आज जरूरत है कि ऑनलाइन गेमिंग की इस समस्या को केवल कानूनी दायरे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी गंभीरता से लिया जाए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को समय पर समझाएं, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें सकारात्मक



योगी आदित्यनाथ

कल्याण मंडपम एक अभिनव पहल



के नाते उसे नौकरी की जरूरत है और पति से उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला है। इस केस में पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि पति-पत्नी दोनों की सिंगापुर में अच्छी नौकरी थी लेकिन बाद में पत्नी ने बच्चों के साथ सिंगापुर लौटने से इंकार कर दिया है। बेंच ने कहा कि पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों का और पत्नी का ख्याल रखे। उन्हें दोनों के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहिए, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़ी महिला ने इससे इंकार कर दिया। महिला ने कहा कि वो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती।

गतिविधियों की ओर प्रेरित करें। समाज को भी मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि मनोरंजन के नाम पर फैल रहे इस जुए की घातक एवं विध्वंसक संस्कृति को बढ़ावा न दिया जाए। यह ठीक है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने का प्रस्ताव पारित कर एक सही दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाया है, लेकिन कानून से भी अधिक जरूरी है जागरूकता। जब तक लोग स्वयं यह नहीं समझेंगे कि गेमिंग का यह जुआ उनके भविष्य को तबाह कर रहा है, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम मनोरंजन के नाम पर छल रही इस प्रवृत्ति का पदार्फाश करें और अपने युवा-ओं को सुरक्षित, रचनात्मक और सकारात्मक भविष्य की राह पर अग्रसर करें। अस्ख्य परिवारों को आज अपने बच्चों की इस आदत के कारण कर्ज और बर्बादी में अंधेरों में जाने से बचाये। खेल के नाम पर ऑनलाइन मंचों पर पैसा लगाना दरअसल सट्टेबाजी ही है, जिसमें जीत की संभावना क्षणिक होती है और हार की संभावना लगभग निश्चित। लाखों युवक अपने खून-पसीने की कमाई या माता-पिता की मेहनत की कमाई को इन कंपनियों की तिजोरियों में डाल रहे हैं। यह समस्या अब जुए की लत से भी अधिक खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि इसमें तकनीक की चकाचीध और आभासी से उपलब्धता ने युवाओं को पहले से ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बीते कुछ वर्षों में तेजी से फैला है। विज्ञापनों, प्रलोभनों और चमकदार ऑफरों ने युवाओं को अपने शिकंजे में इस तरह जकड़ लिया है कि लाखों लोग इसमें डूबकर अपनी शिक्षा, करियर और परिवार तक को दांव पर लगा बैठे हैं। जब खेल केवल मनोरंजन तक सीमित रहता है तब तक उसकी उपयोगिता है, पर जैसे ही इसमें धन और लालच का तत्त्व जुड़ता है, यह जुए में बदल जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से विनाश की शुरुआत होती है। सच्चाई यह है कि ऑनलाइन गेमिंग का जाल इतना व्यापक हो चुका है कि इसे रोकने के लिए कानून की सख्ती के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक हस्तक्षेप भी उतने ही जरूरी हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग के सख्त नियमन और इसे भारी कराधान के अधीन लाना एक व्यावहारिक समाधान होगा। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देकर उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की भी जरूरत है। इस अभियान में गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त प्लेटफॉर्मों पर जुमाना भी लगाना एवं बड़े-बड़े दावे करने वाली मशहूर हस्तियों पर कार्रवाई भी होते हुए दिखनी चाहिए, तभी यह कानून कारगर एवं प्रभावी बन पायेगा।



गोरखपुर (जीकेबी)। सीएम योगी ने कल्याण मंडपम को एक अभिनव पहल बताते हुए कहा कि इसकी शुरुआत गोरखपुर ने की। आज प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली आदि सभी शहर गोरखपुर के कल्याण मंडपम माडल को अपना रहे हैं। कल्याण मंडपम से गरीबों को सुविधा तो मिल ही रही है इसके लिए सभी नगर निगमों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। कल्याण मंडपम के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विकास होता है तो कुछ लोग राजनीति भी करते हैं। उनको प्रदेश और गोरखपुर के विकास से पीड़ा होती



जस्टिस नागरत्ना ने महिला से कहा कि एक बार शादी होने के बाद आप यह नहीं कह सकतीं कि आप पति पर निर्भर नहीं हैं। भले ही आप आर्थिक तौर पर न हो लेकिन भावनात्मक तौर पर तो आप निर्भर होगी ही। जस्टिस नागरत्ना ने यहां तक कहा कि आप ये नहीं कह सकती कि आप किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती। अगर ऐसा था तो फिर आपने शादी क्यों की। हो सकता है कि मैं आपको पुराने विचारों की लग्न लेकिन कोई पत्नी यह नहीं कह सकती कि वो अपने पति पर निर्भर नहीं है।

महिला ने इस मामले में विचार के लिए कोर्ट से वक्त दिए जाने की मांग की। बेंच ने कहा कि आप दोनों पति-पत्नी पढ़े लिखे हैं। आपको बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहिए।

इस मामले में पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो अभी भारत में हैं। 1 सितंबर को वो वापस सिंगापुर लौटेंगे। उसके छोटे बच्चे का जन्मदिन 23 अगस्त को है और वो दोनों बच्चों के साथ इस जन्मदिन मनाना चाहता है। इस पर कोर्ट ने महिला से कहा कि वो जन्मदिन मनाने के लिए दोनों बच्चों को उस दिन पति को सौंप दे। हालांकि कोर्ट ने पति से ये सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चे शाम को अपनी मां के पास जन्मदिन मनाने के लिए घर लौट आए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगस्त में आने वाले वीकेंड पर बच्चे की कस्टडी पिता के पास भी रहेगी। कोर्ट में पति की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए वो अभी तलाक की प्रक्रिया पर रोक लगाने के इच्छुक है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने पति से कहा है कि वो इस दरम्यान महिला और बच्चे के मेंटेंस के लिए 5 लाख जमा करें। कोर्ट आगे 16 सितंबर को सुनवाई करेगा।

एक सामाजिक और जन स्वास्थ्य के लिए घातक समस्या: ऑनलाइन गेमिंग

ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सामाजिक और जन स्वास्थ्य के लिए घातक समस्या है। सरकार के मुताबिक, वह ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये उत्सुक है, जिसमें कोई वित्तीय जोखिम न हो। निर्विवाद रूप से हाल के वर्षों में ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग ने तेजी से विस्तार किया है। जिसमें पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारों के प्रचार को भी भूमिका रही है। यहां उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेमिंग का वार्षिक राजस्व 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इसके साथ ही यह हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। लेकिन इसके साथ चिंता का विषय यह भी है कि सुनहरे सब्जबाग दिखाने वाले कई ऑनलाइन गेमिंग एप लत, खेलने वाले आम लोगों के आर्थिक नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग में अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले बदकिस्मत उपयोगकर्ता नाकामी के बाद आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। निस्संदेह सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा जोखिम भी उठाया है। इसमें सरकार को राजस्व की भारी हानि भी हो सकती है। वहीं तसवीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि कई उद्यमी तेजी से उभरते इस गेमिंग व्यवसाय के पराभव की चिंता जता रहे हैं। यह एक हकीकत है कि ऑन लाइन मनी गेमिंग यदि लत बन जाए तो यह संपन्न व्यक्ति को भी बदहाल कर सकती है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हर साल 45 करोड़ लोग बीस हजार करोड़ गवां देते हैं सब कुछ गंवा कर आत्महत्या करने के मामले भी प्रकाश में आते हैं। सवाल इन लालच जगाने वाली मनी गेमिंग की पारदर्शिता को लेकर भी उठते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं के बाद सरकार ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लेकर आई है। जिसे अब गंभीर चर्चा के बिना संसद ने पारित भी कर दिया है। यह विधेयक पैसे से खेले जाने वाले किसी भी ऑनलाइन गेम को गैरकानूनी घोषित करता है। बताया जाता है कि देश में जो ग्यारह सौ से अधिक गेमिंग कंपनियां तथा करीब चार सौ स्टार्टअप ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़े हैं, जिनके नियमन के बारे में सोचा जा सकता था। उनकी चिंता है कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि उसने जनकल्याण को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। लेकिन दूसरी ओर चिंता जतायी जा रही है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के वैध प्लेटफॉर्म बंद होने से खेलने वाले लोग अनियमित विदेशी ऑपरेटरों के शिकार बन सकते हैं। इंटरनेट का विस्तृत दायरा और विदेशी ऑनलाइन ऑपरेटर विधेयक के प्रमुख उद्देश्यों को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। निस्संदेह, वित्तीय प्रणालियों की अखंडता के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए।

मॉर्निंग वॉक के दौरान आम जन के साथ चाय की चुस्कियां लेते सीएम धामी



देहरादून/चमोली। उत्तराखंड प्रदेश के भराड़ीसैंण में आज सुबह सीएम धामी अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकले और चाय की दुकान पर खुद ही चाय बनाई। दुकान में मौजूद लोगों के बीच बैठ कर चाय की चुस्कियों के साथ सरकार की विक-सापरक योजनाओं के बारे में चर्चा की।

भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद भी सीएम पृक्षर सिंह धामी गैरसैंण में जनता के बीच नजर आए। आज सुबह-सुबह सीएम धामी बिना लाव-लश्कर के भराड़ीसैंण में सैर करने के लिए निकले। इस दौरान इस दौरान सीएम धामी, चंद्र सिंह नेगी की चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बातें करने लगे। इसी दौरान बातों ही बातों में सीएम धामी ही खुद चाय बनाने लग गए। फिर उन्होंने लोगों के साथ बैठकर चाय का आनंद लिया। सीएम धामी ने लोगों से उनका हाल-चाल पूछा और सरकार द्वारा संचालित विकासपरक और जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि "कल विधानसभा सत्र समापन के बाद भराड़ीसैंण में रह कर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है।

लंपी वायरस : किसानों में दहशत, टीकाकरण में जुटा पशुपालन विभाग

बेलीपार, गोरखपुर। बेलीपार क्षेत्र में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। एक साथ सात पशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, जिससे किसानों में दहशत फैल गई है। लक्षणों की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग टीकाकरण की तैयारी में जुट गया है। भत्सा निवासी बृजेश पांडेय, गुल्लुर यादव, गोपी निषाद, पवन यादव, मलांव निवासी गुड्डु शुक्ला, डवरपार निवासी अक्षय निषाद और कनईल निवासी परमात्मा शुक्ल के पशुओं में यह बीमारी पाई गई है। पशुपालकों का कहना है कि गावों के शरीर पर फोड़े और फफोले उभर आए हैं। उन्हें आशंका है कि समय पर टीकाकरण न हुआ तो रोम अन्य स्वस्थ पशुओं में भी फैल सकता है। सेंवई के पशु चिकित्सक डॉ. नरेंद्र कुमार चौधरी के अनुसार, सूचना मिलने पर टीम गांवों में जाकर टीकाकरण करेगी। कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार के पशुपालन वैज्ञानिक डॉ. सतीश कुमार ने बताया कि गांठदार त्वचा रोग (लंपी वायरस) का कोई विशेष एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण ही इसका एकमात्र सुरक्षित उपाय है। संक्रमित पशुओं की विशेष देखभाल करें। घाव बनने पर एंटीसेप्टिक क्रीम, स्रे या पाउडर का उपयोग करें और द्वितीयक संक्रमण होने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें।



है। प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन माहौल से उनको चिढ़ होती है। उनके इन काया का जवाब जनता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें तेजी के साथ हो रहे परिवर्तन का संवाहक बनाना पड़ेगा। आज जब दुनिया आगे बढ़ रही है तब हम जड़तापूर्वक बैठे नहीं रह सकते। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर की सड़कें फोरलेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुकी हैं। हर क्षेत्र में अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के कारण आज गोरखपुर से लखनऊ जाने में केवल तीन घण्टे लगते हैं पहले यही दूरी 7 से 8 घंटों में पूरी होती थी। आज न केवल अच्छी ट्रेन की सुविधा है बल्कि अच्छी

सड़कों के साथ एयर कनेक्टिविटी की भी सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विकास हो रहा है तो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल की गतिविधियों के लिए भी मंच प्रदान कर रही है। गोरखपुर के राप्तीनगर विस्तार योजना में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही है। इसके पहले गोरखपुर के राजेन्द्र नगर पश्चिम में भी बाबा राघवदास के नाम पर मिनी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। वहां पर दो सौ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहां आउटडोर व इण्डोर गेम्स की विभिन्न खेल गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

गजब का टाइम-पास, टॉप क्लास का मनोरंजन

एक समय की बात है- जब अपने विद्यार्थी जीवन का अल्ट्रडपन और लड़कपन था। पड़ोस में कुछ लड़के रहते थे, वे कहीं गांव से शहर में आकर पढ़ाई करने आए थे। कमरा किराए पर लेकर बड़ी मौज में रहते थे। अक्सर आधी-आधी रात तक वह खूब हंसते, कभी रोते और कभी चिल्लाते। एक रोज उनसे पूछा गया भाई क्या मामला है, तुम लोगों का, आधी-आधी रात तक हंसने-गाने-रोने का कौन सा धारावाहिक बन रहा है। तुम लोगों की क्या नौटंकी है ये सब। वे हंसते हुए बोले, जब पढ़ने का मन नहीं होता मन बहुत ऊबने लगता है तब हम लोग चुटकुलेबाजी शुरू करते हैं-धुआंधार हास्य व्यंग्य के लतीफे शुरू करते हैं और तब हंसगुल्लों की बौछार शुरू होती है फिर जब हम हंसगुल्लों से हंसते-हंसते लोटपोट बेहाल हो जाते हैं-पेट पर तमाम बल पड़ने लगता है, तब हम एक-दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, तब हमारी हंसी-ठहाकों का प्रवाहमान सैलाब थमता है। मेरा पूरा सिर नाच गया। मुंह से अक्सर निकल पड़ता है- वाह क्या सीन है। हंसी के मैच में थपड़ की फिक्सिंग। गजब और जीने दो के महान समीकरण पर क्या खूब मनोरंजन का खेल रचाया है। भाई तुम लोगों ने वाह! क्या गजब का टाइमपास, टॉप क्लास का मनोरंजन है। शगल है। बरसों बीते गए, हंसगुल्ले वाले उन लड़कों को। विद्यार्थी जीवन से शुरू हुआ उनका, थपड़-थपड़ में हंसी-ठहाकों और रोने- गाने का खेला- अब कहीं स्याहीफेंक-कहीं जूताफेंक, कहीं कालिख पोत आदि इत्यादि तक की बड़ी पटकथा तक पहुंच चुकी है।

किसी फिल्म में मनोरंज के लिए किशोर कुमार और मो. रफी का गाया एक गाना अचानक याद आने लगा-
वन टू चल शुरू हो जा चला मुक्का
जमा थप्पड़ लगा टक्कर
वन टू चल जरा फिर से गिरा निचे
फसा टंगड़ी लगा लंगड़ी गम न कर पार्टनर-
के साथ अपनी बात को विराम देना पसंद करूंगा।

सड़कों के साथ एयर कनेक्टिविटी की भी सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विकास हो रहा है तो गरीब कल्याण के लिए योजनाएं भी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल की गतिविधियों के लिए भी मंच प्रदान कर रही है। गोरखपुर के राप्तीनगर विस्तार योजना में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही है। इसके पहले गोरखपुर के राजेन्द्र नगर पश्चिम में भी बाबा राघवदास के नाम पर मिनी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। वहां पर दो सौ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहां आउटडोर व इण्डोर गेम्स की विभिन्न खेल गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

जब पढ़ने का मन नहीं होता मन बहुत ऊबने लगता है तब हम लोग चुटकुलेबाजी शुरू करते हैं-धुआंधार हास्य व्यंग्य के लतीफे शुरू करते हैं और तब हंसगुल्लों की बौछार शुरू होती है फिर जब हम हंसगुल्लों से हंसते-हंसते लोटपोट बेहाल हो जाते हैं-पेट पर तमाम बल पड़ने लगता है, तब हम एक-दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, तब हमारी हंसी-ठहाकों का प्रवाहमान सैलाब थमता है।

गजब का टाइम-पास, टॉप क्लास का मनोरंजन

एक समय की बात है- जब अपने विद्यार्थी जीवन का अल्ट्रडपन और लड़कपन था। पड़ोस में कुछ लड़के रहते थे, वे कहीं गांव से शहर में आकर पढ़ाई करने आए थे। कमरा किराए पर लेकर बड़ी मौज में रहते थे। अक्सर आधी-आधी रात तक वह खूब हंसते, कभी रोते और कभी चिल्लाते। एक रोज उनसे पूछा गया भाई क्या मामला है, तुम लोगों का, आधी-आधी रात तक हंसने-गाने-रोने का कौन सा धारावाहिक बन रहा है। तुम लोगों की क्या नौटंकी है ये सब। वे हंसते हुए बोले, जब पढ़ने का मन नहीं होता मन बहुत ऊबने लगता है तब हम लोग चुटकुलेबाजी शुरू करते हैं-धुआंधार हास्य व्यंग्य के लतीफे शुरू करते हैं और तब हंसगुल्लों की बौछार शुरू होती है फिर जब हम हंसगुल्लों से हंसते-हंसते लोटपोट बेहाल हो जाते हैं-पेट पर तमाम बल पड़ने लगता है, तब हम एक-दूसरे को थपड़ मारते हैं, तब हमारी हंसी-ठहाकों का प्रवाहमान सैलाब थमता है। मेरा पूरा सिर नाच गया। मुंह से अक्सर निकल पड़ता है- वाह क्या सीन है। हंसी के मैच में थपड़ की फिक्सिंग। गजब और जीने दो के महान समीकरण पर क्या खूब मनोरंजन का खेल रचाया है। भाई तुम लोगों ने वाह! क्या गजब का टाइमपास, टॉप क्लास का मनोरंजन है। शगल है। बरसों बीते गए, हंसगुल्ले वाले उन लड़कों को। विद्यार्थी जीवन से शुरू हुआ उनका, थपड़-थपड़ में हंसी-ठहाकों और रोने- गाने का खेला- अब कहीं स्याहीफेंक-कहीं जूताफेंक, कहीं कालिख पोत आदि इत्यादि तक की बड़ी पटकथा तक पहुंच चुकी है।

किसी फिल्म में मनोरंज के लिए किशोर कुमार और मो. रफी का गाया एक गाना अचानक याद आने लगा-
वन टू चल शुरू हो जा चला मुक्का
जमा थप्पड़ लगा टक्कर
वन टू चल जरा फिर से गिरा निचे
फसा टंगड़ी लगा लंगड़ी गम न कर पार्टनर-
के साथ अपनी बात को विराम देना पसंद करूंगा।

लोकतंत्र से भिड़ने का खामियाजा उठाएगा विपक्ष...!



लोग अक्सर कहते थे कि, यह आदमी लाल किले की प्राचीर से बोलने लायक नहीं है ! इसमें वह करंट नहीं जो इनके बाप में थी और गंभीरता तो बिल्कुल नहीं है, जिसकी अपेक्षा की जाती है ! इनकी भाषा चुनावी टोन से आगे नहीं जा पाती ! कोसना , कलपना चारित्रिक गुणों की तरह व्यक्तित्व में समाये हुए है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हु जिसने इनका एक भी भाषण लाईव नहीं सुना , न ही कभी बकवास सुनने में समय जाया करने की इक्षा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इन्होने आज देश को वोट चोरी के खुलासे की यंत्रणा दी , काफी उबाऊ , थकाऊ टाइप का अभियान भी चलाएंगे पैदल यात्रा के रूप में , जिसका अंडर करंट दिमाग में चल रही चुनावी खब्त (बिहार और फिर यूपी) को दर्शा रहा। देश इनसे कांग्रेस का नाम सुनना चाहता , चाइना का नाम सुनना चाहता है , वोट चोरी पर स्पस्टीकरण चाहता था लेकिन ये मियां मोदी से आगे नहीं निकल पाए। शिक्षा , रोजगार , स्वास्थ्य पर सरकार को कोसना वैसे भी कभी इनकी प्राथमिकता में नहीं रहे, बिहार में भी नदारद ! हाँ बासी कड़ी में उबाल देने के लिए संघ को कोसना और तिरंगे का सम्मान ना करना ये इनडायरेक्टली बताते है कि इनके पूर्वज मुस्लिम भी थे। इल्जाम बेअसर हो रहे है ! फेक्ट चेकर इनका मुंह खुलते ही सक्रिय हो रहे है , लगभग हर दांव वल्टा पड़ रहा है -शास्त्रों में इसे सम्पूर्ण अंत की शुरुआत भी कहा जाता है ! सूत्रों से खबर है कि यही प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी अपने इंडिया के साथियों के साथ सासाराम जिले के रोहातास से पटना तक सोलह दिनों में लगभग 1300 किमी की पदयात्रा के माध्यम से वोटर के वोट चोरी के खिलाफ 17अगस्त से शुरू आत करने जा रहे हैं। यह प्रयास अपने आपको दूध का धुला बताने का है । एनडीए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन की घोषणा कर चुकि है। इसकी गंभीरता हम समझ सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में समर्थन के नाम पर वही पुरानी चापलूसी मिला है वह इंगित कर रहा है कि बिहार एक बार फिर जनक्रांति के नाम पर ठगे जाने वाला है। विदित हो यह 16 दिवसीय पदयात्रा तकरीबन 23 जिलों से गुजरेगी तथा एक सितम्बर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी।

बिहार में सूत्रों कि माने तो कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने जिस तरह नकेल कस दी है उसमें प्रतिपक्ष नेता बौखला गए है और आम जनता के बीच पहुंच वोट चोरी की झूठी शिकायतों और झूठा प्रचार, बेबुनियादी राजनीति को केवल चुनावी स्टंट बताया गया। चोरी और सीनाजोरी वाले इस रवैए ने विपक्ष में चुनाव आयोग की कटु आलोचना को बढ़ावा दिया है। सबसे बड़ा मजाक तो यह किया गया कि देश की बहू, बेटियों, मां-बहनों के सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की गई है। अखबारों में और टीवी में वे दिखाया जा रहा है जो सच है लेकिन साथ हुए लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी के फर्जी इल्जाम आप यू नहीं देख सकते। अजी कब तक पर्दे में रहस्य रखोगे। पीएम मोदी को अनाप शनाप भाषा बोलोगे। शर्म करो, यह सफाई नहीं अपने देश की सरकार की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट को क्या 65लाख लोगों की सूची भेज उसे सार्वजनिक भी तो कर दिया। कब तक झूठ का दामन पकड़ें हागे देश जा रहा है संभावना है कहीं आप और गत में ना चले जाए। यह पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग जनता के आरोप वोट चोरी की जांच को उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने सीधे सच्चे आचरण के बारे में बता राहुल की पोल खोल गया।जबकि यह भली-भाति जाहिर है कि राहुल पूर्व वित्तमंत्री पी चींदबराम की खोज है। जब आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो आपकी राजनीति दो टुक की हो जाती है। आपके वे साथी टूट पड़ते झूठे आरोप लगाने। यह तो वे ही करते हैं जिन्हें पोल खुलने का खतरा रहता है। उसकी निष्पक्षता के क्या कहने जो मोदी के भाषणों की समाप्ति के बाद जनता को गाली बकना शुरू कर दें। लोकतंत्र ही चुनाव की घोषणा करता है। चुनाव आयोग और सरकार मिलकर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करते है। हमारे वोट के अधिकार की चोरी और उसको छुपाने का प्रयास कभी कोई नहीं कर सकता है फिर इल्जाम क्या ! लेकिन अब कांग्रेस के खिलाफ जन्मा आंदोलन रुकने वाला नहीं। जनता जनार्दन को चाहिए सबसे पहले वह ईवीएम का विरोध करने वालों को हर उस स्टेट से हटवाए जहाँ वो देश विरोधी गतिविधि कर रहे। दूसरा चुनाव आयोग के कार्यों में नेताओ के हस्तक्षेप को बंद कराये। जागो, वरना लोकतंत्र के हत्यारे आपसे यात्रा करवाकर आपका लोकप्रिय नेता चुनने का अधिकार भी धीरे-धीरे जमींदोज कर देंगे। जनता की शक्ति बनी रहे। इसलिए न्याय पाने लड़ें बिना लड़े कुछ हासिल नहीं होगा। खासकर जब क्रूर और असंवेदनशील विपक्ष के साप में हम सब हों। हर असत्य ये शब्द हाल ही में नया चलन में आया है। मामला कुछ यूँ समझिये कि विपक्ष को जब ये महसूस हुआ कि चुनाव में हार रहे है तो उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज मुहैया करवाने का अनुरोध किया जो लोकतंत्र की अवमानना है। उधर चुनाव आयोग जिसे कुछ लोग चूना आयोग तो कुछ लोग केचुआ भी कहते हुए नजर आते हैं, ये वो लोग है जो संविधान की लालकिताब लहराते है। और अंततः विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी और आते ही पहली ही गेंद को लंबा बाउंडर वो भी वाइड बॉल फेंकी, इस ताबड़तोड़ बौलिंग को देखकर जनता सकते में आ गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष इतनी जल्दी ऐसा बाउंडर ले आएगा। जब विपक्ष ने उन कार्यों को नहीं दिखाया जो चुनाव आयोग ने दिए थे लोग सवाल पूछने लगे कि कही चोर मचाए शोर वाली बात तो नहीं। फिर शुरू हुआ फर्जी हवा चलाने कि कोशिस कि कोई आदित्य श्रीवास्तव चार राज्यों में वोट डाल रहा है तो कहीं एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, तो कहीं एक लाख से अधिक फर्जी वोट पाए गए, तो कहीं ऐसे मकान और एड्रेस थे जो वास्तव में कहीं थे ही नहीं। विपक्ष ने मांग की कि उन्हें डिजिटल डेटा दिया जाए, मगर चुनाव आयोग जानता था कि ऐसा करने पर पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। लिहाजा डिजिटल डेटा देने के बजाय जो उपलब्ध था वो भी वेबसाइट से हटा दिया गया। और राहुल गाँधी को ही कह दिया कि आप शपथ पत्र दीजिये। अब राहुल सकते में है। संविधान ने भारत में भारतीय नागरिकों को व्यस्क मताधिकार का अधिकार दिया है। जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है उसे बिना जाति, धर्म, लिंग का भेद किए, चुनाव का अधिकार होगा। लेकिन वही अधिकार अब सड़को पर नीलाम होने लगे तो लोकतंत्र और संविधान के क्या मायने रह जाएंगे। हालांकि इस गंभीर मुद्दे पर मीडिया को राहुल से सफाई मांगनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया का कहना है कि वे राहुल को गंभीरता से नहीं लेते और सवाल करने का कार्य फिलहाल छोड़ चुके हैं अब एक बार छोड़ा गया कार्य वापस पकड़ना मुश्किल है।

पकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

समय का चक्र चला यह कैसा हर तरफ फैला है उसका जाल मोबाइल हो गया बहुत स्मार्ट और आदमी का दिमाग कंगाल समय देखना घड़ी को भूले अलार्म जब चाहें बज जाता दिमाग पर बोझ क्यों डालें जब जमा घटना गुना भाग झट से हो जाता उंगलियों का कमाल है जितना चाहे चलाओ टाइपराइटर को भूल मन में जो आये लिखते जाओ कापी पर लिखने की जरूरत नहीं रही अब जो लिखा है जब चाहे दोबारा पाओ अब तो उंगली को भी नहीं रही जरूरत

मोबाइल ने ऐसा चक्कर चलाया

मुंह से बोलकर सब कुछ है लिख जाता खुशी हो या दुख का हो संदेश कुछ पल में दुनिया भर में पहुंचाता फोन नम्बर किसी को याद नहीं सब यही रखता है अब याद मोबाइल ने ऐसा चक्कर चलाया सब रहना चाहते हैं अब आजाद सुबह उठते ही पहले फोन देखावन बन गया जरूरी भगवान को भी अब बाद में करते हैं याद रिश्ते नातों को भी कहीं का नहीं छोड़ा इसने सदियों पुराने संस्कार भी कर दिए बर्बाद

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवााँ, जिला बिलासपुर हि प्र

संयुक्तपरिवारधीरे-धीरे खत्म हो रहे... और बुजुर्गों के लिए जगह कम होती जा रही

विजय गंग

कुछ लगे समय पहले अयोध्या में दिल दहला देने वाली एक घटना ने भारत में बुजुर्गों की हो रही दुर्दशा सामने रख दी है। कैसर से पीड़ित बुजुर्ग महिला को उसके ही परिवज रात के अंधेरे में ई-रिक्षा में लाद कर सड़क किनारे छोड़ गए। महिला इतनी लाचार थी कि न तो बोल सकती थी और न ही चल सकती थी। यह पूरी घटना पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पता चलता है कि किस तरह एक असहाय महिला को सड़क पर छोड़ दिया गया। बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति बढ़ती उपेक्षा और अमानवीयता की एक ऐसी परत है, जिसकी तह में हम नहीं जाते और अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पारिवारिक मूल्य जो हमें बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाते थे, अब किताबों और रीति-रिवाजों तक ही सीमित रह गए हैं। आज के समय में व्यक्तिवाद अपने चरम पर है और जीवन की गति तीव्र हो गई है, ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी या बोझ के रूप में देखा जाता है।

हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परंपराएं और आधुनिकता आपस में टकरा रही हैं। संयुक्त परिवार धीरे-धीरे खत्म हो रहे है। उसकी जगह ल की संस्कृति ले रही है, जिसमें बुजुर्गों के लिए जगह कम होती जा है। आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उपलब्धियों की ओर अग्रसर आज की पीढ़ी के लिए समय की कमी और सामाजिक प्रतिबद्धताओं की सीमाएं बुजुर्गों की देखभाल को बोझ

बना रही हैं। भारत में बुजुर्गों की जनसांख्यिकी स्थिति भी सामाजिक चुनौती बन रही है। इस समय भारत में 160 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 15 करोड़ तीस लाख लोग हैं और अनुमान कि 2050 तक यह संख्या 34 करोड़ सत्तर लाख तक पहुंच सकती है। वर्ष 2031 तक बुजुर्गों की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 20.1 फीसद तक पहुंचने की संभावना है, जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रपट भी यही संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां और पारिवारिक संरचनाएं भी इस बदलाव से गहराई से प्रभावित होंगी। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों, खास-ाकर केरल और तमिलनाडु में बुजुर्गों का अनुपात सबसे ज्यादा है, जो दशाता है कि इन क्षेत्रों को इस जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने के लिए जल्द से जल्द और प्रभावी रणनीति अपनानी होंगी। स्पष्ट है कि भारत बहुत समय तक युवा राष्ट्र नहीं रह पाएगा। ऐसे में हमारी नीतियों और नजरिए बदलाव जरूरी लेकिन जनसंख्या वृद्धि ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा की समस्या भी भारत में एक गहरे संकट के रूप में उभर रही है। कई अध्ययनों से पता चला है कि घर के अंदर बुजुर्गों की उपेक्षा की दर 47.5 फीसद है, जबकि घर के बाहर यह आंकड़ा 32 फीसद तक पहुंच जाता है।



वर्ष 2022 में 22 शहरों में किए गए एक अध्ययन में 35 फीसद बुजुर्गों ने कहा कि उनके बेटों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, 21 फीसद ने बहुओं को दोषी ठहराया, जबकि दो फीसद ने बाहरी सहायकों को दोषी ठहराया। ये आंकड़े बताते हैं कि वृद्ध जनों की सबसे अधिक उपेक्षा उन्हीं लोगों द्वारा की जा रही है, जिनसे उन्हें सबसे अधिक सुरक्षा और स्नेह की अपेक्षा होती है। महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। पुरुषों की तुलना में वे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का अधिक शिकार होती हैं, खासकर विधवा होने पर जब उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। सरकार योजनाओं के प्रति जागरूकता और पहुंच की बेहद सीमित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में केवल 55 फीसद, विधवा पेंशन योजना के बारे में 44 फीसद और अन्नपूर्णा योजना के बारे में केवल 12 फीसद बुजुर्गों को ही जानकारी है। ये आंकड़े न केवल नीति निर्माण में खामियों की ओर इशारा करते हैं, बल्कि

यह भी दर्शाते हैं कि जागरूकता और क्रियान्वयन स्तर पर हम कितने पीछे हैं। ग्रामीण भारत में स्थिति औ भी भयावह है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नगण्य है और सामाजिक सुरक्षा तंत्र लगभग नदारद है। बुजुर्गों की इस स्थिति का मूल कारण केवल आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में आ रहे बदलाव हैं। संयुक्त परिवार जो कभी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हुआ करते थे, आज बिखर चुके हैं। शहरीकरण और वैश्वीकरण के दौर में युवा बेहतर जीवन की तलाश में शहरों और विदेशों का रुख कर रहे हैं, जिससे बुजुर्ग गांवों या छोटे शहरों में अकेले रह जाते हैं।

मध्यम वर्गीय परिवारों को पहले बुजुर्गों की देखभाल का सबसे मजबूत आधार माना जाता था, अब ये खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इलाज, देखभाल और पुनर्व-सि की बढ़ती लागत उन्हें लाचार बना रही है। महिलाओं की बढ़ती कार्य भागीदारी ने पारंपरिक देखभाल चुनौती दी दी है। पहले महिलाएं घर पर न बुजुर्गों की देखभाल करती थीं, लेकिन आज उनके पास समय का अभाव है। संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर पारिवारिक विवाद भी बुजुर्गों के लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा करते हैं। इन तमाम जटिलताओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य ऐसा विषय है, जिस पर न तो समाज खुल कर बात करता है और न ही सरकार पर्याप्त ध्यान देती है। अवसाद, अकेलापन, चिंता और सामाजिक अलगाव जैसे मुद्दे बुजुर्गों की मूक पीड़ा को और गहरा करते हैं। कई बुजुर्ग

अपनी पीड़ा नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में उनकी कोई आवाज नहीं है। चुप्पी तब एक सामाजिक अपराध में बदल जाती है, जब उनकी उपेक्षा को सामान्य मान लिया जाता है। इसका समाधान सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं निकलेगा। इसके लिए एक समग्र, बहुआयामी और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वृद्ध जनों के लिए राष्ट्रीय नीति का न केवल प्रभावी क्रियान्वयन हो, बल्कि समय पर उसमें संशोधन भी किया जाए ताकि वह वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चला कर सामाजिक सोच में आवश्यक बदलाव लाया जा सकता है। निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से वृद्ध आश्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है और देखभाल के ऐसे तरीके विकसित किए जा सकते हैं जो पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच संतुलन बना सकें।

वृद्ध जनों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में त्वरित न्याय होना चाहिए ताकि समाज को यह स्पष्ट संदेश मिल सके कि उनकी उपेक्षा और शोषण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। परिवारों और समुदाय ऐसी संरचनाएं विकसित की जानी चाहिए जो वृद्ध जनों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बना सकें। यदि हम वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा विकास समावेशी हो। कोई भी बुजुर्ग असहाय, अकेला और उपेक्षित न रहे।

मलौट पंजाब

झूठे मुकदमे केवल निदोषों को पीड़ा नहीं देते, बल्कि न्याय तंत्र की नींव को भी हिला देते हैं। जब वकील ही इस व्यापार में शामिल होते हैं तो वकालत की गरिमा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता दोनों पर गहरा आघात होता है। ऐसे वकीलों पर आपराधिक मुकदमे चलना अनिवार्य है ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। न्याय केवल किताबों में दर्ज प्रावधान नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। यह आस्था तभी बची रहेगी जब न्याय के प्रहरी झ्र वकील और अदालत झ्र स्वयं अपने आचरण से पारदर्शिता और ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।



झूठे मुकदमों का कारोबार और वकीलों की जवाबदेही

भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव सत्य और न्याय पर आधारित है। न्यायालय को हमेशा से समाज का सबसे बड़ा सहारा माना जाता रहा है। जब अन्याय पीड़ित व्यक्ति हर दरवाजे पर ठोकर खाकर थक जाता है, तब उसे अदालत से ही उम्मीद रहती है। लेकिन यह उम्मीद तब कमजोर पड़ जाती है जब न्याय का सहारा बनने वाले लोग ही उसे अपने स्वार्थ और लालच का साधन बना लेते हैं। हाल ही में लखनऊ की अदालत ने एक वकील परमानंद गुप्ता को 29 झूठे मुकदमे दर्ज कराने के अपराध में उम्रकैद और पाँच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एक उदाहरण है कि न्यायपालिका कानून का दुरुपयोग करने वालों को बख्शेगी नहीं। यह केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं है, बल्कि पूरे समाज या न्यायिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है कि कानून का मजाक उड़ाने वालों की कोई जगह नहीं।

वकील पेशे को समाज में हमेशा सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। वकील को केवल मुवक्कल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि न्यायालय का अधिकारी भी माना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन जब वही वकील झूठे मुकदमों का निर्माण करने लगे, निदोषों को फँसाने लगे, और अपने पेशे का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या आर्थिक लाभ के लिए करने लगे, तो यह न केवल उसकी आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि पूरे पेशे की गरिमा पर भी प्रसंछिद्द है। एक वकील की अदालत में सत्य का पक्षधर होना चाहिए, अगर असत्य का सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो समाज में न्याय की कोई गारंटी नहीं रह जाती। झूठे मुकदमों का असर केवल आरोपित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह उसके परिवार, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति तक को झकझोर देता है। वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत जुटाने पड़ते हैं और मानसिक यातना करने से झेलनी पड़ती है। समाज की ऐसे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और धीरे-धीरे कानून और अदालत पर से विश्वास उठने लगता है। यहीं सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि न्याय पर से भरोसा खत्म होना किसी भी समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है।

झूठे मुकदमों की समस्या यह भी है कि यह असली पीड़ितों के मामलों को कमजोर करती है। जब कोई

कानून, जैसे एससी-एसटी एक्ट, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, झूठे मुकदमों में इस्तेमाल किया जाता है तो वास्तविक पीड़ितों की आवाज दब जाती है। अदालतों को यह तय करने में अधिक समय लग जाता है कि कौन-सा मामला सच है और कौन-सा झूठा। नतीजा यह होता है कि असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देर होती है और उनका दर्द बढ़ जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि झूठे मुकदमे गढ़ने वाले और उन्हें अदालत में आगे बढ़ाने वाले वकीलों पर कठोरतम कार-वाई हो। यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करता है, तो उस पर केस चलता है। यदि कोई इंजीनियर खराब निर्माण करता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो फिर वकील, जो न्याय के प्रहरी हैं, यदि झूठे मुकदमों का व्यापार करें, तो उन्हें भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने जैसी धाराओं में दंडित किया जाना चाहिए। उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए और बार काउंसिल को उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए।

यह केवल कानून की सख्ती का मामला नहीं है, बल्कि वकालत के पेशे की मर्यादा का प्रश्न है। जब तक झूठे मुकदमों के निर्माण और संचालन में शामिल वकीलों पर मुकदमे नहीं चलेंगे, तब तक यह कुप्रथा बंद नहीं होगी। अदालतें जितनी कठोर सजा देंगी, उतना ही यह संदेश समाज में जाएगा कि कानून का दुरुपयोग करने वालों की कोई जगह नहीं।

न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यक है कि कानून में ऐसे प्रावधान हों जिससे झूठे मुकदमों की पहचान होने पर तुरंत कार्रवाई हो। वकीलों की जवाबदेही तय करनी होगी। अगर यह साबित हो कि किसी वकील ने जानबूझकर मुवक्कल को झूठे मुकदमे के लिए उकसाया, तो उस पर केवल पेशेवर कार्रवाई न हो बल्कि अपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। इस कदम से न केवल निदोष लोगों की रक्षा होगी बल्कि वकालत का पेशा भी अपने वास्तविक उद्देश्य झ्र न्याय की सेवा झ्र के लिए जाना जाएगा। आज लखनऊ की अदालत का फैसला पूरे देश के लिए मिसाल है। इसने साबित किया है कि न्यायालय केवल आरोपी और अपराधी के बीच निर्णय करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की पवित्रता को भी सुरक्षित रखने वाला प्रहरी है। यदि वकील अपने कर्तव्य से भ्रंशकेंगे, तो वे भी अपराधी की श्रेणी में आएँगे और उन्हें उसी प्रकार दंड मिलेगा जैसे अन्य

धोखाधड़ी के शिकार होते बुजुर्ग

लखनऊ की 65 वर्षीय रजनी (काल्पनिक नाम) अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थीं। उनके पति एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। जो कुछ वर्ष पूर्व ही गुजर गए थे। पति की बचत (पेशन) ही रजनी की जिंदगी का सहारा थी। उनकी बेटियाँ शादी के बाद आपनी जिंदगी हमें खुशहाल, और व्यस्त हैं। एक दिन रजनी को कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को वेल्थ मैनेजमेंट कमेटी का कर्मचारी को बताते हुए कहा कि- सिर्फ पचास हजार निवेश करें और हर महीने दस हजार रुपए की गारंटी शुदा आप पाएंगे रजनी ने इस अवसर को अपनी बचत बढ़ाने का मौका समझा। भरोसा करके ऑन लाइन फार्म भरकर पचास हजार रुपए का निवेश किया। कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने कहा आपके निवेश ने 20 प्रतिशत मुनाफा दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आप पांच लाख रुपए डालें तो रिटर्न और बड़ा होगा। रजनी ने जब अपनी लगा रकम को निकालने की सोची तो उसने आनाकानी की और बाद में नंबर बंद हो गया। पुलिस के पास जाने पर पता चला कि रजनी साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई है।

रजनी की यह कहानी उन लाखों सीनियर सिटीजन की कहानियों में से एक है जो वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार आए दिन होते रहते हैं। इसका कारण - बुजुर्गों (सीनियर सिटीजन) के पास रिटायर के बाद अच्छी खासी काय होती है। तकनीकी चीजों के साथ वे बहुत ज्यादा (टेक फ्रेंडली) नहीं होते हैं। साइबर फ्राड के बारे में अधिक जानकारी नहीं होने भय-और लोभ किसी भी व्यक्ति को साइबर ठगों के जाल में फंसाती है। डिजिटल युग में साइबर अपराधी नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को (खास कर बुजुर्गों को) अपना शिकार बना रहे हैं जिनक विचार यहां पर किया जाता है। फिशिंग स्कैम - धोखेबाज फार्सी ई-मेल: मैसेज या फोन कॉल के जरिए सीनियर सिटीजन को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड या अन्य वित्तीय खाते खतरे में हैं। वे ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी मांगते हैं। कई लोग इन जाल साजों के झांसे में आकर ठगों का शिकार हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट : डिजिटल अरेस्ट ऐसी धोखाधड़ी है जिसमें साइबर अपराधी रक्त को पुलिस, सीबीआई या अन्य कानूनी एजेंसी का अधिकारी बता कर डराते हैं। फर्जी मुकदमे में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसा ऐंठते हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भी मन की बात में कई बार डिजिटल अरेस्ट के विषय पर चर्चा कर चुके हैं। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी: कई बार साइबर अपराधी आकर्षक रिटर्न का लालच देते हैं जैसे- डबल योर मनी, तेजी से अमीर बनने वाली स्कीम, फिर फर्जी ट्रेंडिंग के जरिए शेयर और म्यूचुअल फंड में योजनाएं अक्सर फर्जी होती हैं और निवेश किया गया पैसा कभी वापस नहीं मिलता।

रिश्तेदार बनकर धोखाधड़ी : साइबर जालसाज बुजुर्गों को फोन करके बताते हैं कि उनके रिश्तेदार या परिचित का एक्सीडेंट हो गया है या फिर वा किसी अपराध में फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए तुरंत पैसे भेजने होंगे। मिस सेलिंग : बिक्री एजेंट या ठग बुजुर्गों को किया पॉलिसी, निवेश योजनाओं या अन्य वित्तीय उत्पादों के बारे में गलत या अधूरी जानकारी देते हैं। इस तरह ऐसी पालिसी या स्कीम बेची जाती है, जो उनकी जरूरतों के अनुरूप होगी।

संयुक्तपरिवारधीरे-धीरे खत्म हो रहे... और बुजुर्गों के लिए जगह कम होती जा रही





किसानों को तुलना नहीं यूरिया चाहिए

केंद्र की मोदी सरकार ने बीते वर्ष-2019 में चुनाव से पहले ही किसान सम्मान विधि की योजना की लांचिंग के माध्यम से ग्रामीण वोटरों को सर्वाधिक प्रभावित किया। यही कारण है कि- किसान सम्मान निधि और पुलवामा ने भाजपा की झोली में 303 सीटें डाल दीं। किसान सम्मान 15 विधि में प्रत्येक जोत वाले किसान को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं जिन्हें तीन किशतों में डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन) के माध्यम से दिया जा रहा है।

भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसमें कृषि के योगदान की अवहेलना नहीं की जा सकती है। 70 प्रतिशत लोग अभी भी गांवों से रहते हैं और खेती की ओर उनका झुकाव बना हुआ है। भले ही रोजी-रोटी के लिए दूसरे शहरों में क्यों न चले जाते हों लेकिन खेती के समय वे गांव आते हैं और अपनी खेती करते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती उसे स्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत में उर्वरकों में सबसे ज्यादा खपत यूरिया की होती है। फसल कोई भी (रबी, खरीफ की क्यों नहीं इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। वही रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन के तनाव के चलते यूरिया का आयात कम हो रहा है। चीन से हमारी निर्भरता पचास फीसदी की थी जो घट गई है क्यों कि उसने अपने यहां निर्यात घटा दिया है। सरकार दावा करती है कि हम यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। निर्माण संयंत्र



राजनीतिक सामाजिक सरोकारों को समेटती पुस्तक

निहाल अजमत चौधरी की समीक्षाधीन पुस्तक में 14 अध्याय हैं जो लेखक के यायावरी जीवन को भी उकेरती हैं। यायावरी इसलिए कि वे कहीं बेच कर नहीं रहे हैं। कभी वकालत की कभी नौकरी की कभी राजनीति कभी खेतीबारी। जीवन के आठ दशकोपरान्त यह पुस्तक प्रकाश में आई जो उनके राजनीतिक सामाजिक सरोकारों को समेटे हुए है। राजनीतिक बलों के टिकट देने का देने का सवाल हो, चुनाव लड़ने या जीतने का सवाल हो। अपने स्वानुभव एवं निजी संबंधों से प्राप्त जानकारी को बड़ी ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है।

पुस्तकीय. अमरुख पूर्व प्रो. रमेश दीक्षित (राजनीति विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय) ने लिखा है। यह पुस्तक मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का भी प्रतिबिंब है। विदेश में राजनीतिक परिवर्तन 'किस प्रकार से मुसलमानों' पर प्रभाव पड़ता रही रहा है। वे भले ही कुछ न कहते रहे हों लेकिन जो महसूस करते हैं वह उस समाज का बयान भी है। जो कुछ सामने होता है शायद उससे कहीं अलग उन मनोभावों की प्रस्तुति इस पुस्तक में मिलती है। वह चाहे जिला के जिन्ना के अलग देश पाकिस्तान के प्रश्न पर भयातुर पढ़े लिखे धनी मुसलमानों का पाकिस्तान को लेकर नजरिया रहा

बढ़े हैं। उत्पादन बढ़ा है। आयात और निर्यात का गैप कम हुआ है। फिर भी किसानों को लंबे समय तक लाइन में लड़ना पड़ रहा है और पुलिस को लाठियां खानी रही हैं। हमारा अन्नदाता है जो लाठियां खा कर भी खेतों में उत्पादन बढ़ाने में प्रयासरत है। इन दिनों यूरिया की खाद की मांग कर रहे किसानों को लाठियां खानी पड़ रही है क्योंकि वे अपनी खेती में खरीफ की फसलों (धान और गन्ने) के अच्छे उत्पादन के लिए, यूरिया के लिए सहकारी समितियों पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं फिर भी जरूरी नहीं कि उनका नंबर आ ही जाए जिन किसानों को अन्नदाता कहा जाता है वही लाठियां खा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसल के लिए खाद ले जाना है। यह स्थिति सिर्फ इस बार के लिए ही नहीं रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए समान है जब किसानों को यूरिया के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। और इसका उत्पादन और वितरण सरकार के नियंत्रण में है।

नेपाल से जुड़े सीमावर्ती जिलों में स्थितियां और भी खराब है क्योंकि जो उपलब्धता होती भी है, वह तस्करी के माध्यम से नेपाल पहुंच जाती है क्योंकि उसका पांच से लेकर दस गुना तक दाम मिल जाता है। सहकारी समितियों पर खड़े होने वाले लोगों में बुजुर्ग व महिलाएं भी हैं। कईयों की तो लाइन में खड़े खड़े मृत्यु भी हो जा रही है। कहीं टोकन मिलता है तो कहीं लोग लाइन में लगे लगे वापस आ जाते हैं।

निहाल अजमत चौधरी की पुस्तक 'यादों के साथे : चंद यादें कुछ दिलचस्प किस्से' 'आत्मकथात्मक शैली में' लिख गई पुस्तकीय आत्मकथ्य है। हरदोई के संडीला से लेकर देश दुनिया की सैर और राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में घुले मिले अनुभवों ने पुस्तक को ऊँचाइयां प्रदान कीं क्योंकि अनेक घटना क्रम के लेखक स्वयं साक्षी रहे हैं।

सरकार

ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहकारी समितियों पर खाद की निजी लाइसेंस दुकानों पर भी इसके बिक्री की व्यवस्था करती है लेकिन इन दुकानों पर से खाद लेने में समस्या यह है कि- किसानों को अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ती है साथ ही साथ वे दूसरी खाद भी लेना अनिवार्य बना देते है लेकिन वास्तव में यदि इन दुकानों पर यूरिया की उपलब्धता होती है तो किसान कुछ अधिक देकर वहाँ से ले लेता।

सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि - प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। वे आज पिछली सरकार से तुलना करते हैं- हमारी सरकार में इतनी उपलब्धता है जबकि पिछली सरकार में ऐसा नहीं था। यदि आठ साल के बाद भी मुख्यमंत्री यही तर्क देते हैं तो गैरवाजिब है। किसानों को तुलना नहीं चाहिए यूरिया की उपलब्धता चाहिए। आज प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है तो जिम्मेदारी आपकी है कि- मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध करावें। किसान लाठियां खाने की बजाय लाइनों में खड़े होकर अपने खेतों में उर्वरक डाल कर अपने उत्पादन को अच्छा बनाएं। केन्द्र सरकार ने नैनो यूरिया का बड़े जोर-शोर से प्रचार किया था लेकिन वह किसानों के भरोसे पर खरी नहीं उतरी। यही कारण है कि सरकार ने नैनो यूरिया की चर्चा करनी ही बंद कर दी।



के गलत ऑपरेशन की बाण है से उनकी पत्नी जाते-जाते बची लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लाखों खर्च करने बाद भी न्याय नहीं मिल सका।

इस पुस्तक में एक वाक्या नगर निगम का पढ़ने को मिलता है कि नगर निगम के चुनाव में किस प्रकार से प्रत्याशी (कांग्रेस) को 32 हजार वोट अवैध करा कर हरा दिया। लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि - यदि मुसलमान तरक्की चाहते हैं तो उन्हें धार्मिकता की भावना से फैसला लेने की बजाय पढ़ाई-लिखाई-और दूसरे धर्मों के बारे में और दूसरे धर्मों के लोगों से भी संबंध बनाए रखने चाहिए। वे मौलानाओं के चक्कर में आकर अपनी पूरी पीढ़ी बरबाद न करें। शहबाज बानों के मामले में किस प्रकार पर्सनल लॉ बोर्ड की भी खूब मजमूत की है कि किस प्रकार से बोर्ड ने देश के मुसलमानों को उकसाने का काम किया है। बोर्ड की बनावट पर ही लेखक ने सवाल उठाए हैं कि उसमें मौलानाओं की ही भरमार रही है विशेषज्ञों की नहीं।

पुस्तक कहीं-कहीं पर बेहद निजी तौर पर अपने आस पास के लोगों का बयान करती है। और अचानक देश दुनिया का बात करती है। इस प्रकार से इस पुस्तक में तमाम उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं।



हो कि जबतक गांधी, नेहरू हैं तबतक सुरक्षित है नहीं तो आरएसएस उन्हें निवाला बना लेगी क्योंकि- कांग्रेस में भी आर एस एसके लोग हैं।

पुस्तक में लेखक ने खुद को ज्यादा धार्मिक बताकर हज, उमरा और साई करने के रिवाज और वहां की स्थितियों का उल्लेख भी किया है कि किस प्रकार स्कूल पर बैठकर उपरा किया जा सकता है। लेखक ने राजनीति से लेकर जुडिशियरी तक की स्थितियों का वर्णन इस पुस्तक में किया है। किस प्रकार से डॉक्टर

जेल की अवधारणा अपराधी में नागरिक उत्तरदायित्व बोध का विकास

जेल की अवधारणा का विकास का मकसद-भटके लोगों के जीवन में सुधार ही रहा होगा। किसी सभ्य समाज के कायदे-कानून तोड़ने वाले, भटके हुए लोगों को जेल के एकाकी जीवन में आत्ममथन का समय देने का भी मकसद रहा होगा। साथ ही वह भी अहसास कराना होगा कि समाज से विलग रहने के क्या मायने हैं। वहीं दूसरी ओर जीवन मूल्यों व सामाजिकता का अहसास कराना भी मकसद रहा होगा। दरअसल, भारतीय न्याय संहिता, 2023 पर आधारित नई व्यवस्था छोटे अपराधों के लिए दोषियों को जेल भेजने के बजाय समाज सेवा करने का अवसर देती है। ताकि उन्हें अपनी गलती का अहसास हो और उत्तरदायित्व के साथ सामाजिकता का बोध हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा जारी सामुदायिक सेवा दिशानिर्देश, 2025 की अधिसूचना आपराधिक न्यायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। जिसका लक्ष्य दंड देने के बजाय सुधार व बदलाव है। ऐसे समय में जब देश की जेलें कैदियों की निर्धारित संख्या से कहीं अधिक बोझ उठा रही हैं।

विचाराधीन कैदियों की संख्या 76 फीसदी से अधिक है, राज्य की यह पहल कम जोखिम वाले अपराधियों के लिये कारावास का सकारात्मक विकल्प प्रदान करती है। निस्संदेह, इस पहल का दायरा व्यापक होने के साथ ही उद्देश्यपूर्ण भी है। यह व्यवस्था कम संगीन अपराधों के

लिये दोषियों को पाकों के रखरखाव, अस्पतालों में मरीजों की सहायता करने, आंगनवाडियों में योगदान देने, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, स्वच्छ भारत तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों में योगदान के लिये प्रेरित करती है। इस बाबत जारी दिशा-निर्देश किशोरों के लिये भी भूमिकाएं निर्धारित करते हैं। मसलन, नेशनल कैडिट कोर प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सेवा योजना, पर्यावरण परियोजनाएं तथा महिलाओं के लिये प्रसूति वार्ड व शिशु देखभाल केंद्र जैसे सुरक्षित स्थानों पर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। निश्चय ही नई व्यवस्था जहां एक ओर अपराधियों को उनके अपराध का प्रार्थित करने का अवसर प्रदान करती है, वहीं समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देती है। दरअसल, हरियाणा मॉडल के तहत की जाने वाली पहल, उसे अन्य राज्यों के प्रयासों से विशिष्टता प्रदान करती है जैसे कि दिल्ली में 40 से 240 घंटे की सेवा निर्धारित करने वाली नीति से अलग, इसके परिचालन का विवरण, इसे विश्वसनीय बनाता है। इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैग की गई तस्वीरें, वीडियो प्रमाण और प्रगति रिपोर्टिंग सत्यापन इस-की सार्थकता सुनिश्चित करती है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को गौशालाओं और वृद्धाश्रमों में सेवा करने की सजा और जम्मू की एक अदालत द्वारा अपराधियों को स्वास्थ्य केंद्र और पार्क की

सफाई करने के लिये बाध्य करने का आदेश यह दशात है कि सामुदायिक सेवा समाज को लाभ पहुंचाने के साथ ही भटके व्यक्ति के व्यवहार को कैसे नया रूप दे सकती है।

निस्संदेह, इस सुधार अभियान को सफल बनाने के लिये सुरक्षा उपाय भी बेहद जरूरी है। इस बात में सावधानी बरती जानी चाहिए कि समाज में बार-बार अपराध करने वालों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाए। दूसरा, इससे जुड़ी निगरानी पारदर्शी और मजबूत होनी चाहिए। जिसमें सावधानी से निगरानी और चूक करने पर त्वरित दंड की व्यवस्था भी शामिल है। दूसरा उनके कार्य के परिणाम का मूल्यांकन होना चाहिए अभियुक्त अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का भी मूल्यांकन होना चाहिए क्या पीड़ितों को इस तरह की सजा दिए जाने से राहत मिली है। यह भी कि क्या समाज में अपराध की पुनरावृत्ति कम हुई है। यह इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष है कि छोटी-मोटी गलतियों को यह सामाजिक ऋण चुकाने के अवसर में बदल देता है। साथ ही कारावास से होने वाले नुकसान को कम करता है। कई बार जेल के हालात, विषम परिस्थितियों में भूलवश अपराध करने वाले व्यक्ति को पेशेवर अपराधी बना देते हैं। नई पहल से अपराधी में नागरिक उत्तरदायित्व बोध का भी विकास होता है।



राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और वहां भाजपा के शीर्ष चेहरों में गिने जाते हैं। उनका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनना भाजपा की यह घोषणा है कि वह दक्षिण भारत को अब हाशिए पर नहीं, बल्कि सत्ता की मुख्यधारा में लाना चाहती है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के मजबूत संगठनकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन उत्तर भारत के भाजपा के राजनीतिक गलियारे में राधाजी के नाम से जाने जाते हैं।

राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से कई हित संधेंगे

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग ने चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करके एक तीर से अनेक निशाने साधे हैं। भाजपा ने बहुत सोच-समझकर उन्हें इस प्रतिष्ठित पद का उम्मीदवार बनाया है। वे तमिल हैं, पिछड़े, भी हैं, संघ से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने करीबी एवं साफ-सुथरी छवि वाले राजनायक हैं। भाजपा ने जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो यह केवल राजनीतिक गणित का परिणाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का निर्णय था, जो सादगी, ईमानदारी और सेवा की पहचान रखते हैं। उनका चयन भारतीय लोकतंत्र की व्यापकता और समावेशिता का जीवंत प्रतीक है।

अब तक भारतीय राजनीति में दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में भाजपा की जड़ें अपेक्षाकृत कमजोर और सबसे बड़ी चुनौती रहा है। उत्तर और पश्चिम भारत में लगातार सफलता के बाद पार्टी चाहती है कि दक्षिण के राज्य भी उसके प्रभाव में आएँ। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और वहां भाजपा के शीर्ष चेहरों में गिने जाते हैं। उनका उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनना भाजपा की यह घोषणा है कि वह दक्षिण भारत को अब हाशिए पर नहीं, बल्कि सत्ता की मुख्यधारा में लाना चाहती है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के मजबूत संगठनकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। सीपी राधाकृष्णन उत्तर भारत के भाजपा के राजनीतिक गलियारे में राधाजी के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु की कोयंबटूर लोकसभा सीट से 1998 और 1999 के आम चुनावों में भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए सीपी राधाकृष्णन ने स्कूली जीवन से ही आरएसएस का दामन थाम लिया था। हालांकि एक दौर में वे तमिल राजनीति में अन्नाद्रमुक के करीब माने जाते थे। उनके तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मधुर संबंध हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में डीएमके की उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना कठिन हो सकता है।

उपराष्ट्रपति पद पर उनका चयन ओबीसी समाज को सम्मान और सशक्तिकरण का नया संदेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार इस वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया है। राधाकृष्णन ओबीसी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ह्रासबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वाससह की नीति को बल दिया है। राधाकृष्णन का चयन इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे भाजपा को देशभर में ओबीसी समाज का और अधिक समर्थन मिल सकता है। इससे भाजपा की सामाजिक आधारशिला और मजबूत होगी। भाजपा अपने निर्णयों से हमेशा करिश्मा घटित करती रही है, अपने चतुराई का परिचय देती रही है, सीपी. राधाकृष्णन का चयन भाजपा की इसी रणनीतिक चतुराई का ही बड़ा उदाहरण है। इससे पार्टी ने एक तीर से अनेक निशाने साधे हैं, दक्षिण भारत में पैठ बनाना, ओबीसी समाज को साधना, विपक्ष को असहज करना और साफ-सुथरी राजनीति का संदेश देना। यह तय है कि उपराष्ट्रपति के रूप में वे न केवल भाजपा बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए सफल नायक सिद्ध होंगे।

यह एक संयोग की कहा जायेगा कि देश के शीर्ष दो पदों पर विराजमान हस्तियों का नाता झारखंड से रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने से पहले झारखंड की राज्यपाल रहें और देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे सीपी राधाकृष्णन भी इस राज्य के राज्यपाल रहे हैं। इन दिनों वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वे झारखंड के साथ ही तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं। मोदी-शाह का उन पर बड़ा भरोसा रहा है, क्योंकि उन्हें एक समय एक साथ तीन-तीन राज्य के राज्यपालों की जिम्मेदारी थमाई गई थी। अभी उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे ही भरोसेमंद, निष्ठाशील एवं जिम्मेदार व्यक्ति की ही तलाश थी। उपराष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, शरीर करते हैं। राधाकृष्णन का अध्ययनशील स्वभाव, शांतता व्यवहार और संतुलित दृष्टिकोण भारत की सौंप पावर की और मजबूत करेगा। उनका व्यक्तित्व भारत की परंपरा, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करेगा।

भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा के सभापति ही नहीं होते, बल्कि सर्वदलीय संवाद और

लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षक भी होते हैं। राधाकृष्णन का सौम्य व्यक्तित्व, धैर्य और संवाद क्षमता उन्हें इस भूमिका में और अधिक सफल बनाएगी। विपक्षी दलों के लिए भी उनकी छवि स्वीकार्य है, जो संसद की कार्यवाही को संतुलित बनाए रखने में सहायक होगी। सी.पी. राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद पर चयन भारतीय लोकतंत्र की उस विशेषता को रेखांकित करता है, जिसमें सादगी और सेवा जैसे गुण सर्वोपरि माने जाते हैं। वे न केवल दक्षिण भारत और ओबीसी समाज का सम्मान हैं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए आशा और संतुलन का चेहरा हैं। निश्चित रूप से वे उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते हुए आने वाले वर्षों में एक आदर्श और प्रेरक नायक सिद्ध होंगे। जैसाकि पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे आदर्श नायक हैं।

वैसे भी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन के बीच कुछ उल्लेखनीय समानताएं दिखाई देती हैं। भले ही दोनों की पृष्ठभूमि अलग हो, एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनयिक रहे, तो दूसरे राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, फिर भी उनके व्यक्तित्व में कई साझा बिंदु हैं जैसे दोनों का नाम द्वाराधाकृष्णनहू है, जो भारतीय संस्कृति में श्रीकृष्ण से जुड़ी भक्ति, ज्ञान और नीति का प्रतीक है। दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय परंपरा और मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को विश्वपटल पर प्रतिष्ठा दिलाई और शिक्षा जगत को नई दिशा दी। सी.पी. राधाकृष्णन ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सेवा, ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए ख्याति अर्जित की। डॉ. राधाकृष्णन जीवन भर शिक्षक रहे और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मूल आधार माना। सी.पी. राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन भी शिक्षा, नैतिकता और संस्कारों की धरती पर खड़ा है। वे स्वच्छ छवि और सादगी के लिए जाने जाते हैं। दोनों का जीवन साधारण परंतु ऊँचे आदर्शों से जुड़ा रहा। किसी प्रकार का दुराचार या विवाद इन दोनों के जीवन में नहीं जुड़ा, जो आज के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बहुत दुर्लभ है। डॉ. राधाकृष्णन को दार्शनिक-राजनेता के रूप में विश्वभर में सम्मान मिला। सी.पी. राधाकृष्णन को जनता का भरोसा, सरल व्यवहार और समाज में उनकी स्वीकार्यता ने एक सम्मानित नेता बनाया। डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक दृष्टिकोण को स्थापित किया। सी.पी. राधाकृष्णन भी राजनीति में समन्वयकारी, सर्वसमावेशी और राष्ट्रहित की सोच को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही भारतीय मूल्यों, ईमानदारी और राष्ट्र-सेवा के प्रतीक माने जा सकते हैं।

राजनीति में सी.पी. राधाकृष्णन की पहचान एक स्वच्छ और सादगीपूर्ण नेता की है। वे कभी भी विवादास्पद राजनीति का हिस्सा नहीं बने, बल्कि अपने संगठन कोशाल, जनता से जुड़ाव और सेवाभाव से अपनी अलग जगह बनाई। सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहने के कारण उनका व्यक्तित्व सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा। यही कारण है कि वे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। भाजपा ने राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर विपक्ष के लिए कठिनाई खड़ी कर दी है। उनकी सादगीपूर्ण और निर्दोष छवि के कारण विपक्ष उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने में हिचकेगा। साथ ही, वे किसी विवाद या कट्टरपंथी राजनीति से दूर रहे हैं, जिससे उनकी स्वीकार्यता सर्वदलीय स्तर पर अधिक है। वे न केवल चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं। इससे भाजपा की यह छवि और प्रखर होगी कि वह स्वच्छ और ईमानदार नेतृत्व को प्राथमिकता देती है। राधाकृष्णन क्यों सफल उपराष्ट्रपति साबित होंगे, इस प्रश्न का उत्तर निम्न पंक्तियों में समाया है कि वे पक्षपात से दूर और सर्वदलीय संवाद को बढ़ावा देने वाले विरल व्यक्तित्व माने जाते हैं। भाजपा संगठन में लंबे अनुभव के कारण वे राजनीतिक नब्ब को भली-भाँति समझते हैं। इससे जनता और सभी दलों में उनकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। दक्षिण भारत का केन्द्र में समुचित प्रतिनिधित्व होने से वे राष्ट्रीय राजनीति में समावेशिता का चेहरा बनेंगे।



हरियाणा की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, कोर्ट में उलझाने की रणनीति

हरियाणा में शिक्षकों की तबादला नीति लंबे समय से विवादों का विषय रही है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हर सरकार शिक्षकों को पारदर्शी और न्यायपूर्ण तबादला नीति का आश्वासन देकर भी उसे लागू करने में विफल होती रही है। नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी भी उसी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होती है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो देखने में तो सुधारवादी लगते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति शिक्षकों के हितों को साधने के बजाय उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझाने के लिए बनाई गई है। यह नीति न केवल शिक्षकों की व्यावसायिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करती है बल्कि उनके पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिरता को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करती है।

पॉलिसी की रूपरेखा और घोषित प्रावधान

नई नीति में सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी शिक्षक का एक ही विद्यालय में अधिकतम ठहराव पाँच वर्ष तक ही रहेगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि ब्लॉक स्तर पर पंद्रह वर्ष से अधिक समय तक कोई शिक्षक नहीं रहेगा। सरकार का दावा है कि यह प्रावधान शिक्षकों को स्थानांतरण का समान अवसर देने और एक ही स्थान पर लंबे समय तक टिके रहने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि बाल देखभाल अवकाश अर्थात चाइल्ड केयर लीव की अवधि को ठहराव की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने तबादलों को पाँच चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में प्राथमिक और जेबीटी शिक्षकों के अंतरजिला तबादले होंगे। दूसरे चरण में मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए तबादले किए जाएंगे। तीसरे चरण में प्रिंसिपल, हेड मास्टर और ब्लॉक स्तर के प्रमुख अधिकारियों के तबादले होंगे। चौथे चरण में पीजीटी और टीजीटी सहित अन्य रेगुलर शिक्षकों के तबादले होंगे और अंत में पाँचवें चरण में गेस्ट टीचर्स को स्थानांतरित किया जाएगा।

कागज पर यह व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुनियोजित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें कई विरोधाभास और असंगतियाँ हैं, जो न केवल शिक्षकों को निराश कर रही हैं बल्कि नीति की पारदर्शिता और सरकार की नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रही हैं।

कपल केस अंक हटाने का असंवेदनशील निर्णय

इस नीति की सबसे बड़ी और विवादास्पद खामी कपल केस अंक को पूरी तरह हटा देना है। अब तक की नीतियों में यह व्यवस्था थी कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो उन्हें एक ही जिले या समीपस्थ स्थान पर तैनात करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। इसका उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं बल्कि परिवार को एक साथ रखने और पति-पत्नी के संयुक्त पारिवारिक जीवन की रक्षा करना था। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को यह निर्देश दिए थे कि कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी में कपल केस को मान्यता दी जाए और अंक दिए जाएं। अन्य विभागों ने इस दिशा-निर्देश का पालन भी किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे नजरअंदाज करते हुए कपल केस अंक को ही समाप्त कर दिया। यह न केवल विभागीय अवमानना है बल्कि शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ है। पति-पत्नी को दूर-दूर नियुक्त करने का सीधा अर्थ है परिवार को तोड़ना, बच्चों के पालन-पोषण को प्रभावित करना और सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त करना। यह निर्णय शिक्षकों के पारिवारिक अधिकारों पर कुठाराघात है और इसे पूरी तरह से संवेदनहीन कहा जा सकता है। निश्चय ही यह प्रावधान न्यायालय में चुनौती जाएगा और शिक्षकों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

पाँच वर्ष और पंद्रह वर्ष का विरोधाभास

नीति में दूसरा बड़ा विरोधाभास यह है कि विद्यालय में अधिकतम ठहराव पाँच वर्ष का है जबकि ब्लॉक में पंद्रह वर्ष का। जब एक शिक्षक को हर पाँच वर्ष में विद्यालय बदलना ही है तो उसे पंद्रह वर्ष

तक एक ही ब्लॉक में बांधकर रखने का औचित्य क्या है। यह प्रावधान न तो प्रशासनिक दृष्टि से तर्कसंगत है और न ही शिक्षक हितैषी है। यदि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को समान अवसर देना है तो ब्लॉक स्तर पर भी ठहराव की अवधि पाँच या अधिकतम सात वर्ष तय की जानी चाहिए। पंद्रह वर्ष तक किसी को एक ही ब्लॉक से बांधे रखना शिक्षकों की पेशेवर स्वतंत्रता और कैरियर विकास पर गंभीर आघात है। यह नियम केवल औपचारिकता प्रतीत होता है, जिसका वास्तविक लाभ न तो विद्यार्थियों को मिलेगा और न ही शिक्षा व्यवस्था को।

कोर्ट में उलझाने की रणनीति

नई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधान इस प्रकार बनाए गए हैं कि यह निश्चित रूप से न्यायालय में चुनौती जाएंगे। कपल केस अंक हटाना, ब्लॉक स्तर पर अव्यावहारिक ठहराव, तबादला चरणों की जटिलता और चयन प्रक्रिया की अस्पष्टता झूठे सभ्य ऐसे बिंदु हैं जो किसी भी समय कानूनी विवाद का कारण बन सकते हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार जानबूझकर ऐसी नीतियाँ बना रही है जिन्हें अदालत में चुनौती मिले और मामला वर्षों तक लंबित रहे। इस तरह सरकार एक ओर तो दावा करती रहेगी कि उसने पारदर्शी नीति बनाई है, वहीं दूसरी ओर अदालत में मामला लंबित होने के कारण वह वास्तविक तबादले करने से बच निकलेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान शिक्षकों को होगा, जिन्हें वर्षों तक तबादले का इंतजार करना पड़ेगा।

शिक्षकों की पीड़ा और असंतोष

शिक्षकों के बीच इस नीति को लेकर गहरा असंतोष है। लंबे समय से शिक्षक संगठन सरकार से पारदर्शी नीति की मांग कर रहे हैं। लेकिन हर बार सरकार या तो वादाखिलाफी करती है या ऐसी नीति बनाती है जो शिक्षकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। कपल केस अंक का समाप्त होना शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा झटका है। महिलाएँ शिक्षिकाएँ हों या पुरुष शिक्षक, सभी अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की

देखभाल और पति-पत्नी के संयुक्त जीवन का महत्व केवल शिक्षक ही समझ सकता है। लेकिन सरकार ने इन सभी संवेदनाओं को दरकिनार कर दिया है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षक और उनका परिवार नहीं बल्कि केवल राजनीतिक लाभ और प्रशासनिक दिखावा है।

नीयत और नीति दोनों संदिग्ध

सरकार ने बार-बार घोषणा की कि नई पॉलिसी पारदर्शी और डिजिटल होगी, लेकिन जब तक नीयत साफ नहीं होगी, तब तक कोई भी नीति शिक्षकों के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। नीति की भाषा और सरकार के वादे जितने चमकदार हैं, उसकी वास्तविकता उतनी ही खोखली है। यही कारण है कि शिक्षकों का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है। नीति के हर प्रावधान में असंगति और विरोधाभास दिखाई देता है। कपल केस अंक हटाना संवेदनहीनता है, ब्लॉक ठहराव अव्यावहारिक है और चरणवार प्रक्रिया जटिल है। इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार ने शिक्षकों की आवाज को अनसुना किया है। संवाद और सहमति के बजाय एकतरफा निर्णय लेकर नीति थोप दी गई है। हरियाणा की नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों की अपेक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था की जरूरतों झूठों पर खरी नहीं उतरती। इसमें न तो पारिवारिक जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और न ही पेशेवर स्वतंत्रता का। यह नीति केवल कोर्ट-कचहरी के मामलों को जन्म देगी और शिक्षकों को निराशा और हताशा के गर्त में धकेलेगी। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की आवाज को गंभीरता से सुने और एक ऐसी नीति बनाए जो वास्तव में पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यावहारिक हो। कपल केस अंक को पुनः बहाल करना, ब्लॉक ठहराव की अवधि पर पुनर्विचार करना और नीति को सरल तथा स्पष्ट बनाना आज की आवश्यकता है। अन्यथा यह नीति भी केवल जुमलेबाजी और खोखले वादों का पिटारा साबित होगी, जिससे न शिक्षा व्यवस्था को लाभ होगा और न ही शिक्षकों को राहत।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका विषयक व्याख्यानमाला

गोरखपुर। यदि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए तो भारत 2011 तक विश्व युवा केवल डिग्री और नौकरी व क सीमित न रहे। बल्कि समाज के पति अपनी जिम्मेदारी समझें। यह बातें एडीजी जोन अशोक सुधा जैन ने शनिवार को एमपी इंटर कालेज में राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथजी महाराज की 11 वी पुण्य तिथि पर व्याख्यान माला में कहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका विषयक व्याख्यानमाला को बतौर मुख्य वक्ता वक्ता अशोक सुधा जैन ने कहा कि- तकनीक और डिजिटल साक्षरता- का उपयोग करते वे सामाजिक बदलाव के अगुवा बन सकते हैं। स्टार्ट अप व सामाजिक उद्यमिता से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि असमानताओं को भी कम किया जा सकेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एनडीए कड़वासरा, पुणे के पूर्व प्रो. डा. राजेन्द्र भारती, ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव जागृत करना है। एमपी शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे छिपी महंत दिग्विजयनाथ महाराज की दूरदर्शिता को याद करते हुए कहा कि इस संख्या के लक्ष्य सदैव युवाओं को स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान से ओत प्रोत कर राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार बना रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डा. अरुण कुमार सिंह तथा संचालन साहित्य परिषद के संयोजक संजय कुमार सिंह ने किया।

'भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी शिक्षा व महंत अवेद्यनाथ'



गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर स्थित गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पुण्यस्मृति में 'भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी शिक्षा व महंत अवेद्यनाथ' विषय पर व्याख्यान गोष्ठी हुई। मुख्य वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी ने कहा कि महंत अवेद्यनाथ सामाजिक समरसता के अग्रदूत होने के साथ ही नारी शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे।

प्रो. त्यागी ने कहा कि महंत अवेद्यनाथ अपनी विचारधारा के प्रति इतने दृढ़ थे कि एक बार उनके मित्र तत्कालीन पुरी पीठ के शंकराचार्य ने नारियों को वेद की शिक्षा देने से मना करने की बात कही तो उन्होंने उनका जमकर विरोध किया। संयोजक डॉ. अभिषेक पांडेय ने कहा कि नारी शिक्षा न केवल एक परिवार के लिए ही आवश्यक है बल्कि एक विकसित राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। अध्यक्षता गोरक्षपीठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की।

फिल्म जगत की संपूर्ण हलचल को रेखांकित करने का प्रयास रहस्यमयी और रोमांचक प्रेम कथा

लेखिका हिमाद्री समर्थ की वर्ष 2024 में प्रकाशित कृति ‘ दिल में बसे हो’ रहस्यमयी रोमांचक प्रेम कथा है जो उन्होंने 4 वर्षों में लिखी। साल 2020 में इस कथानक को उन्होंने लिखना शुरू किया था तब इसका नाम कृष्णा की राधिका रखते हुए कहानी के ढांचे पर काम करना शुरू किया था। दिल में बसे हो एक रहस्य में रोमांचक प्रेम कथा है जिसे फिल्म की पटकथा के रूप में कुल 101 दृश्य में समाहित कर लिखा गया है। पटकथा प्रारूप में लिखी इन कहानियों में माया नगरी मुंबई के फिल्म जगत की संपूर्ण हलचल को रेखांकित करने का प्रयास है, इसमें पटकथा लेखिका अनुराधा के संघर्ष की रोमांचक प्रेम कथा है, जिसमें फिल्म की तमाम विधाओं में काम करने वाले किरदारों की कामयाबी और विफलताओं का चित्रण किया है।

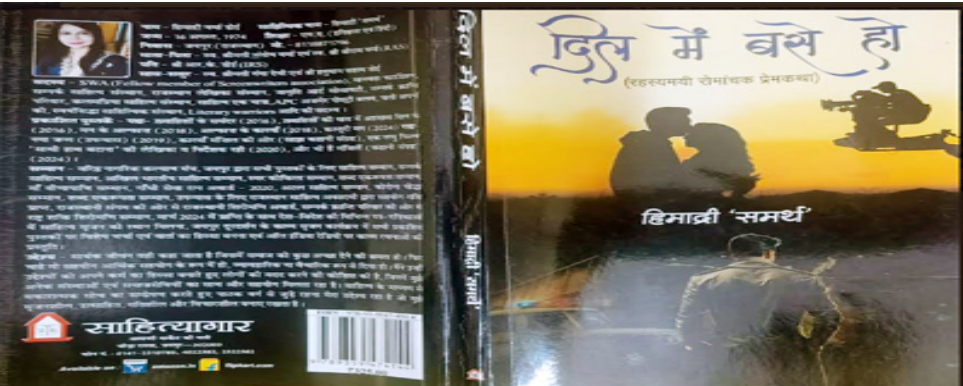
कई लोगों को फिल्म जगत में बरसों बीत जाते हैं लेकिन संघर्ष के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त से हो जाते हैं। प्रस्तुत पटकथा इन्हीं विषयों पर केन्द्रित है। दिल में बसे हो लेखिका की 4 वर्षों की तपस्या का प्रतिफल है , जिसे वह मन के उद्गार के अंतर्गत लिखती है ।

महानगर मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर है जहाँ लोग बड़े सपनों को साकार करने जाते हैं। जहां लोग एक्टर ,डायरेक्टर, सिंगर ,म्यूजिशियन, स्क्रिप्ट राइटर बनने जाते हैं। प्रस्तुत कृति हमारे समाज में घटित होने वाली विभिन्न अकल्पनीय घटनाओं का प्रारंभ से अंत तक पढ़ने को मजबूर करती है रहस्यमयी प्रेम कथा बड़ी रोचक व हृदयस्पर्श घटनाओं को संजोए क्रमिक घटनाक्रमों का सुंदर संयोजन लगती है ।

कहानी के मुख्य किरदार कृष्णा, राधिका, अनुराधा और देव हैं वहीं सहायक किरदारों में बाबूलाल, रोशनी, रोहन ,साइमन, मानसी, अंकिता, रमेश सोनिया सुधीर और सुधा है इस कृति में कहानी के साथ ही फिल्म दिल में बसे हो पटकथा में हिमाद्री समर्थ ने साथ गीत भी लिखे हैं फिल्म की रोमांचक प्रेम कथा पाठकों को प्रारंभ से अंत तक पढ़ने को मजबूर करती है रहस्यमयी प्रेम कथा बड़ी रोचक व हृदयस्पर्श घटनाओं को संजोए क्रमिक घटनाक्रमों का सुंदर संयोजन लगती है ।

जयपुर शहर की सुनहरी शाम के दृश्य 1 से प्रारंभ होने वाली ‘दिल मे बसे हो’ की पटकथा लोनावाला में शूटिंग दृश्य 101 पर समाप्त होती है।

कहानी में बताया कि राधिका फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर बनने हेतु मुंबई अपना भाग्य आजमाती हैं वह देव शर्मा सब इंस्पेक्टर की पत्नी



है 20 वर्षीय लवली उसके घर की नौकरानी है। जो घर की साफ सफाई खाना बनाने का काम करती है। इधर राधिका को एक फोन आता है कृष्णा सिंघानिया का ,जो कृष्णा फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाता है। वह कहता है मैं आपके कंटेस्ट से प्रभावित हुआ हूँ इस पर काम किया जा सकता है जिसे सुनकर राधिका रहती है मैं आपकी फैन हूँ। आपने कितनी हिट फिल्में दी है इसके बावजूद भी आप में जरा भी अभिमान नहीं। राधिका अपनी सहेली अंकिता के घर रुकती है लेकिन वह कहती है मेरे सपने मुझे मुंबई बुला रहे हैं अब तो जाना ही होगा। वह अंकिता के घर से रवाना होती है वह सुबह मुंबई अपने घर पहुंच जाती है जहां देव उसे बाहों में भर लेता है इतने में कृष्णा का फोन आता है। वह अगले दिन उससे मिलने का वादा करती है। अगले दिन राधिका कृष्णा के ऑफिस जाती है।

एग्जीमेंट की फॉर्मिलिटी पूरी करने की बात होती है। वह घर जाकर देव को बताती है कि प्रोड्यूसर कृष्णा सिंघानिया को उसकी लिखी स्क्रिप्ट पसंद आ गई है। फिर राधिका म्यूजिक डायरेक्टर विशाल मेघवाल से मुंबई में मिलने जाती है जहां राधिका के पेट दर्द होता है उसे विशाल हॉस्पिटल ले जाता है। जहां उसका 4 महीने का डिस्कैन्ज हो जाता है। अगले दिन राधिका कृष्णा के ऑफिस जाकर पेपर साइन कर लेती है। उसी दिन से वह ऑफिशियल स्क्रीन प्ले राइटर बन जाती है।

कृष्णा राधिका को फिल्म साइन होने की खुशी में शाम को पार्टी

देता है। पार्टी में उसे कॉलेज के दोस्त रोहन, रोशनी मिलते हैं रोहन भी स्क्रीन टेस्ट देने आया हुआ है। यह जानकर कहती है अरे आज डांस फ्लोर पर तीनों फ्रेंड्स जमकर डांस करते हैं। राधिका जब देर रात घर पहुंचती है तो देव नाराज होता है। फिर स्क्रीन टेस्ट होता है जिसमें कृष्णा राधिका के टैलेंट की प्रशंसा करता है। कहानी में आगे राधिका की किडनैपिंग हो जाती है। जिसका पूरा आप मीडिया के जरिए देव कृष्णा पर लगता है। शहर में सोनिया का मर्डर हो जाता है। 25 वर्ष पहले मुंबई में जब अनुराधा स्क्रिप्ट राइटर कृष्णा के ऑफिस आती है यह सब कहानी कृष्णा राधिका को अपनी कहानी सुनाता है। अनुराधा और कृष्णा बात करते हैं। जहां अनुराधा की लिखी कहानी सेलेक्ट नहीं होती है लेकिन वह 10 दिन में ही नई स्क्रिप्ट लिखकर लाती है। वह धीरे-धीरे अनुराधा के करीब आता है और उसे जीवन सँगिनी बनने की चाहत व्यक्त करता है। अनुराधा कृष्णा से 4 साल बड़ी है। 25 वर्ष पूर्व होली के दृश्य की शूटिंग का दृश्य का वर्णन आता है। फिर अनुराधा का एक्सीडेंट हो जाता है। वह आईसीयू में भर्ती होती है।

सिटी हॉस्पिटल गोरगांव में वह अंतिम सांस लेती है। राधिका की किडनैपिंग के बाद देव उसे खोजने हेतु नाकाबंदी करता है। इसी बीच रोशनी का मर्डर हो जाता है। अदालती कैसे चलता है जहाँ जज साहब कहते हैं कि तमाम सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सब इंस्पेक्टर देव ने अपनी पत्नी

को अगवा कर मारने की कोशिश की। सोनिया व एक्ट्रेस रोशनी को ड्रम्स की हैवी डोज देकर मारा है। साथ ही जुर्म छुपाते के लिए महेश व रोहन को जेल भेजने का अपराध किया है। मानसी सिंघानिया इस जुर्म में बराबर हिस्सेदार है। जिसने 22 वर्ष पूर्व अनुराधा का एक्सीडेंट कराया था। देव अदालत में पिस्टल चलता है। जहाँ वह स्वयं गोली मार लेता है। इंस्पेक्टर देव कृष्ण व राधा को आपस में एक दूसरे का हाथ थामने की कहता है। देव दम तोड़ देता है। राधिका व कृष्णा हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। दोनों नायक नायिका के स्थान पर खुद को इमेजिन कर लोनावला में शूटिंग लोकेशन पर पहुंच कर रंगरेजा गीत फिल्माया जाता है और इस पटकथा का अंत हो जाता है।

सारांशतः पटकथा बड़ी रोचक व क्रमिक घटना क्रमों का सुंदर गुलदस्ता है जिसकी महक दिल को छू लेती है ।

पटकथा लेखन एक कहानी को फिल्म या किसी अन्य दृश्य माध्यम के लिए अनुकूलित करने की एक प्रक्रिया है। यह एक विशिष्ट तकनीकी विधा है जो कहानी को दृश्य में बदल देती है संवाद लिखती है और अभिनेताओं की शारीरिक क्रियाओं का वर्णन करती है। प्रस्तुत पाठ कथा 101 दृश्य में विभाजित है, जो एक कहानी या फिल्म के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती है। पटकथा में लेखिका ने संवाद के साथ ही पात्रों की शारीरिक क्रियाओं का जीवंत वर्णन किया है। दृश्य और सेटिंग का विवरण परिवेश के अनुकूल लगा। पटकथा में तकनीकी भाषा का प्रयोग शब्दों व वाक्यांशों का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया है। पटकथा की भाषा सरल व स्पष्ट है। हिमाद्री समर्थ की रहस्यमई रोमांचक प्रेम कथा में कहानी कहने की क्षमता, संवाद लेखन की कुशलता, दृश्य के प्रति समझ और लचीलापन, सृजनात्मकता, अनुभव का आत्मविश्वास दृष्टिगत होता है। मैं इस कृति हेतु आदर्शनीया हिमाद्री समर्थ जी को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने रहस्यमयी रोमांचक प्रेमकथा के रूप में मायानगरी मुंबई की फिल्मी दुनिया में भाग्य आजमाने जा रहे लोगों की सफलता असफलता को दर्शाने का सार्थक प्रयास किया है। पटकथा में निहित सात गीत इंद्रधनुषी रंगों से दिल को छू जाते हैं।

-डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित

समीक्षक
भवानीमंडी जिला झालावाड़ राजस्थान



स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र :

ghoonghatkibagawat37@gmail.com